गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 296
दि. 27.02.2026,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

संवेदनशील मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त संदेश, न्याय और पर्यावरण सुरक्षा को दी सर्वोच्च प्राथमिकता

जीएनएस)। देश की न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशीलता को सर्वोपरि मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गुरुवार को तीन महत्वपूर्ण और व्यापक प्रभाव वाले मामलों में कड़ा रुख अपनाया। इन मामलों में मणिपुर में हुई जातीय हिंसा के पीड़ितों के अधिकार, अरावली पर्वतमाला की सीमा और संरक्षण से जुड़ा पर्यावरणीय विवाद, तथा प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत से संबंधित याचिका शामिल हैं। अदालत के इन कदमों को न्यायिक सक्रियता और संवेदनशील मामलों में न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक निर्णायक पहल के रूप में देखा जा रहा है।

मणिपुर हिंसा के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि न्याय केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसमें पीड़ितों की सक्रिय भागीदारी और जानकारी का अधिकार भी शामिल है। अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो और राज्य की विशेष जांच टीमों को निर्देश दिया कि जिन मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, उनकी प्रतियां सीधे पीड़ितों और उनके परिवारों को उपलब्ध कराई जाएं। अदालत ने कहा कि किसी भी पीड़ित को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि न्याय प्रक्रिया उससे दूर है या उसे जानकारी से वंचित रखा जा रहा है। यह निर्देश उस स्थिति रिपोर्ट के आधार पर दिया गया, जिसमें बताया गया था कि कई मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, लेकिन पीड़ितों को उसकी जानकारी नहीं दी गई थी।

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस बात पर भी जोर दिया कि जांच एजेंसियां समयसीमा का पालन करें और लंबित मामलों की जांच को जल्द से जल्द पूरा करें। अदालत ने कहा कि न्याय में देरी, न्याय से वंचित करने के समान है और विशेष रूप से ऐसे मामलों में, जहां लोगों ने अपने परिजनों

को खोया है और जीवन में गहरे घाव सहे हैं, वहां न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक संवेदनशील और प्रभावी बनाना आवश्यक है। अदालत के इस रुख से यह स्पष्ट संदेश गया है कि पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और उन्हें न्याय प्रक्रिया से अलग नहीं रखा जा सकता।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित किया कि पीड़ितों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए। अदालत ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश दिया कि ऐसे वकीलों की नियुक्ति की जाए जो स्थानीय भाषा समझते हों और पीड़ितों के साथ प्रभावी संवाद स्थापित कर सकें। अदालत ने यह भी कहा कि पीड़ितों को अदालत में उपस्थित होने के लिए यात्रा और ठहरने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी, जिसका खर्च संबंधित प्राधिकरण वहन करेंगे। यह कदम न्याय को अधिक सुलभ और मानवीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

अरावली पर्वतमाला से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी गंभीरता को स्पष्ट किया। अदालत ने संकेत दिया कि इस क्षेत्र की सटीक परिभाषा और सीमा निर्धारित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जा सकता है। अदालत ने फिलहाल इस क्षेत्र में चल रही गतिविधियों, विशेष रूप से खनन से संबंधित लाइसेंस और कार्यों पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि अरावली केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं है, बल्कि यह देश के पर्यावरणीय संतुलन, जल संरक्षण और जैव विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है।

अदालत की इस टिप्पणी को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। अरावली पर्वतमाला उत्तर भारत के कई राज्यों में फैली हुई है और यह क्षेत्र भूजल स्तर को बनाए रखने, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक विशेषज्ञ समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करती और अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इस क्षेत्र में कोई नई गतिविधि शुरू नहीं की जा सकती।

इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने सोनम वांगचुक की हिरासत से संबंधित याचिका पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया। अदालत ने इस मामले की अंतिम सुनवाई की तारीख निर्धारित करते हुए स्पष्ट किया कि अब इस मामले में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। अदालत ने कहा कि यह मामला व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका शीघ्र और निष्पक्ष समाधान आवश्यक है। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि सुनवाई के दौरान यदि कोई संदेह या प्रश्न उठता है, तो उसे उसी समय स्पष्ट किया जाएगा और मामले को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के इन तीनों मामलों में दिए गए निर्देशों से यह स्पष्ट होता है कि अदालत न्याय और संविधान के मूल सिद्धांतों की रक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। चाहे वह हिंसा के पीड़ितों को न्याय दिलाने का मामला हो, पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा हो या किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा प्रश्न, अदालत ने हर मामले में संतुलित और सख्त दृष्टिकोण अपनाया है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के ये कदम न्याय व्यवस्था में विश्वास को मजबूत करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी नागरिक के अधिकारों की अनदेखी न हो। अदालत का यह रुख यह भी दर्शाता है कि वह केवल कानूनी विवादों का समाधान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के व्यापक हितों और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए भी सक्रिय भूमिका निभा रही है।

इन फैसलों से यह संदेश भी गया है कि देश की सर्वोच्च अदालत न्याय, पर्यावरण और नागरिक अधिकारों के संरक्षण के प्रति पूरी तरह सजग और प्रतिबद्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि न्याय केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है, और इस जिम्मेदारी को निभाने में कोई भी समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

हवाई यात्रियों को बड़ी राहत, टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर रद्द करने पर मिलेगा पूरा रिफंड

जीएनएस)। हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण और राहतभरी खबर सामने आई है। देश के विमानन नियामक नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने एयरलाइन टिकट रिफंड से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिससे अब यात्रियों को टिकट बुक करने के बाद निर्णय बदलने की स्थिति में अधिक सुविधा और सुरक्षा मिलेगी। नए नियमों के अनुसार, यदि कोई यात्री टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर अपनी टिकट रद्द करता है या उसमें संशोधन करता है, तो उसे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के यह सुविधा मिल सकेगी, बशर्ते निर्धारित शर्तों का पालन किया गया हो।

इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को अधिक पारदर्शिता और लचीलापन प्रदान करना है, क्योंकि पहले यात्रियों को टिकट बुक करने के तुरंत बाद बदलाव करने पर भी भारी शुल्क देना पड़ता था। कई बार यात्रियों से नाम की मामूली गलती सुधारने या यात्रा योजना बदलने के लिए भी अतिरिक्त शुल्क वसूला जाता था, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था। अब नए नियमों के तहत यदि यात्री टिकट बुकिंग के 24 घंटे के भीतर अपने नाम में कोई त्रुटि पाता है और टिकट सीधे एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट से बुक किया गया है, तो एयरलाइन को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उस गलती को सुधारना होगा।

DGCA ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि टिकट किसी ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन

पोर्टल के माध्यम से खरीदी गई है, तो भी रिफंड की जिम्मेदारी संबंधित एयरलाइन की ही होगी। इसका कारण यह है कि ट्रैवल एजेंट और पोर्टल एयरलाइन के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए अंतिम जिम्मेदारी एयरलाइन पर ही आती है। इसके साथ ही DGCA ने एयरलाइनों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि टिकट रद्द होने की स्थिति में रिफंड प्रक्रिया अधिकतम 14 कार्यदिवसों के भीतर पूरी कर दी जाए, ताकि यात्रियों को लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े।

नए नियमों में चिकित्सा आपात स्थिति को भी विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है। यदि किसी यात्री या उसके परिवार के सदस्य को अचानक गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो जाती है और यात्रा रद्द करनी पड़ती है, तो एयरलाइन को ऐसे मामलों में सहानुभूतिपूर्ण और लचीला दृष्टिकोण अपनाना होगा। यह प्रावधान यात्रियों की वास्तविक परिस्थितियों को समझते हुए बनाया गया है, ताकि आपात स्थिति में उन्हें अतिरिक्त आर्थिक बोझ न झेलना पड़े।

DGCA ने एयरलाइनों के लिए एक नया 'लुक-इन' विकल्प भी अनिवार्य कर दिया है। इस विकल्प के तहत टिकट बुकिंग के बाद 48 घंटे तक यात्री को यह अधिकार होगा कि वह बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपनी टिकट रद्द कर सकता है या उसमें बदलाव कर सकता है। यदि यात्री उड़ान की तारीख या समय में परिवर्तन करता है, तो उसे केवल नए टिकट का लागू किराया देना होगा, लेकिन रद्दीकरण या संशोधन शुल्क नहीं देना पड़ेगा। यह सुविधा यात्रियों को अपनी यात्रा योजना को अंतिम रूप देने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करेगी।

हालांकि, यह सुविधा सभी उड़ानों पर लागू नहीं होगी। DGCA ने स्पष्ट किया है कि यह नियम केवल उन टिकटों पर लागू होगा, जिनकी यात्रा तिथि बुकिंग की तारीख से कम से कम सात दिन बाद की हो, यदि वह घरेलू उड़ान है, और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के मामले में यह अवधि कम से कम 15 दिन होनी चाहिए। यदि यात्रा की तारीख इससे कम अवधि में है, तो एयरलाइन को यह सुविधा प्रदान करना अनिवार्य नहीं होगा। इसके अलावा, 48 घंटे की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद यदि यात्री टिकट रद्द करता है या संशोधन करता है, तो उसे एयरलाइन की सामान्य रद्दीकरण और संशोधन शुल्क नीति के अनुसार शुल्क देना होगा।

यह संशोधन ऐसे समय में किया गया है जब पिछले कुछ समय से यात्रियों की शिकायतें लगातार बढ़ रही थीं। कई यात्रियों ने आरोप लगाया था कि टिकट रद्द करने के बाद उन्हें समय पर रिफंड नहीं मिल रहा था या उन्हें अनावश्यक शुल्क देना पड़ रहा था। विशेष रूप से दिसंबर 2025 में उड़ानों में व्यवधान के दौरान यह मुद्दा प्रमुखता से सामने आया था, जब बड़ी संख्या में यात्रियों को रिफंड पाने में कठिनाई का सामना करना पड़ा था। इसके बाद सरकार और विमानन मंत्रालय ने इस मामले को गंभीरता से लिया और यात्रियों के हित में नए नियम लागू करने का निर्णय लिया।

नए नियमों के लागू होने से यात्रियों और एयरलाइनों के बीच विश्वास बढ़ने की उम्मीद है। यह कदम न केवल यात्रियों के अधिकारों की रक्षा करेगा, बल्कि एयरलाइनों को भी अधिक पारदर्शी और जिम्मेदार बनने के लिए प्रेरित करेगा। इससे विमानन क्षेत्र में ग्राहक सेवा के स्तर में सुधार होगा और यात्रियों को अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद अनुभव मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव भारतीय विमानन क्षेत्र में एक सकारात्मक सुधार है, जिससे यात्रियों को आर्थिक सुरक्षा और मानसिक संतोष मिलेगा। अब यात्रियों को टिकट बुक करते समय यह डर नहीं रहेगा कि यदि उनकी योजना बदल जाती है तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।

सूरत की राष्ट्रीय राष्ट्रीय समिति में भर्ती विवाद: स्वाति देसाई की नियुक्ति और योग्यता पर सवाल उठे

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। सूरत नगर निगम में स्मीयर अस्पताल के गठन के बाद नए कर्मचारियों की भर्ती की गई। इनमें कक्षा 4, कक्षा 3, तकनीकी कर्मचारी और नर्सिंग स्टाफ की तत्काल भर्ती की गई। इसके साथ ही, मेडिकल कॉलेज से तत्काल स्वीकृति प्राप्त करके कर्मचारियों की भर्ती करना आवश्यक हो गया। इस स्थिति में, लाग्गागिया और चाचा-चाची, पिता-पुत्र के पद पर कार्यरत कर्मचारियों को नियुक्त किया गया। इसी भर्ती में, स्वाति देसाई, जो वर्तमान में डीएम कमिश्नर के पद पर हैं, लगभग चालीस कर्मचारियों के साथ बिना किसी भर्ती प्रक्रिया के क्लर्क के रूप में शामिल हुईं। इसके बाद, जब उन्हें अवसर मिला, तो सूरत नगर निगम में सचिव के पद के लिए उनका चयन हो गया। और कुछ वर्षों बाद, वे पिछले 3 वर्षों से सूरत नगर निगम में डीएम कमिश्नर के पद पर कार्यरत हैं।

शून्य त्रुटि विज्ञापन

सूरत नगर निगम की नीतियों और नियमों के अनुसार, कार्मिक अधिकारी, सहायक आयुक्त और उप आयुक्त (गैर-तकनीकी) कर्मचारियों/अधिकारियों के पास एलएलबी की डिग्री होना अनिवार्य है। यह एक निर्धारित योग्यता है। कार्मिक अधिकारी और सहायक आयुक्तों को आमतौर पर उप आयुक्तों में शामिल किया जाता है, क्योंकि उनके पास एलएलबी की डिग्री होती है। क्या स्वाति देसाई ने सूरत नगर निगम में कार्यभार संभालने से पहले एलएलबी की पढ़ाई पूरी की थी या उन्होंने कार्यभार संभालने के बाद एलएलबी की पढ़ाई की? यह जांच का विषय है। सूरत नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ऐसी चर्चा है कि स्वाति देसाई ने अपने वर्तमान कार्यकाल के दौरान एलएलबी की डिग्री प्राप्त की है।

स्वाति देसाई ने इस शर्त पर अपना इस्तीफा वापस ले लिया कि उन्हें किसी अन्य क्षेत्रीय कार्यालय में तैनात नहीं किया जाएगा और वे केवल अपने पसंदीदा विभागों में ही काम करेंगी तथा लेखा का काम उन्हीं के पास रहेगा। अंततः उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया और एमएनपी को दबाव डालकर पद पर बनी रहीं। सूरत एमएनपी की ऐसी क्या मजबूरी है कि इतनी अधिक बेरोजगारी के बीच, जहां अनेक योग्य उम्मीदवार बेरोजगार हैं, स्वाति देसाई को पद पर बनाए रखा गया है?

यहां सवाल यह है कि क्या कोई गॉडफादर स्वाति देसाई को गुपचुप तरीके से बचा तो नहीं रहा है और कहीं वह अपने स्वार्थ के लिए ऐसा तो नहीं कर रहा है? दरअसल, कई सवाल उठते हैं, लेकिन उनके जवाब देने के लिए एमएनपी के पदाधिकारी या उच्च अधिकारी फिलहाल चुप रहने की नीति अपना रहे हैं और आपके और मैरी के बारे में चुप्पी साधे हुए हैं।

सूरत के बिल्डर की आत्महत्या ने खड़े किए नए सवाल, WhatsApp चैट से परिवार और महिला मित्र के आरोपों की जंग तेज

जीएनएस)। गुजरात के सूरत में चर्चित बिल्डर तुषार गेलानी की आत्महत्या का मामला अब एक नए और जटिल मोड़ पर पहुंच गया है। शुरुआत में जहां इस घटना के पीछे उनकी महिला मित्र पूनम भदोरिया पर मानसिक प्रताड़ना और ब्लैकमेलिंग के गंभीर आरोप लगाए गए थे, वहीं अब पूनम ने अदालत में पेश अपनी जमानत याचिका में ऐसे खुलासे किए हैं, जिन्होंने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी है। पूनम ने न केवल खुद को निर्दोष बताया है, बल्कि तुषार के अपने परिवार, खासकर उनकी बड़ी बेटी पर मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है।यह पूरा मामला 1 फरवरी से शुरू हुआ, जब 58 वर्षीय तुषार गेलानी ने अपनी बेटी की शादी की तैयारियों के बीच अचानक खुद को गोली मार ली। इस घटना से परिवार, रिश्तेदार और पूरा कारोबारी जगत स्तब्ध रह गया। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चार दिन तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद 5 फरवरी को उन्होंने अंतिम सांस ली। इस घटना के बाद तुषार की बड़ी बेटी ने पूनम भदोरिया के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और उन पर लंबे समय से मानसिक प्रताड़ना, ब्लैकमेलिंग और आर्थिक शोषण के आरोप लगाए।

शिकायत में कहा गया कि पूनम पिछले 15 वर्षों से तुषार के संपर्क में थी और उनके

साथ अनैतिक संबंधों का फायदा उठाकर उन्हें बदनाम करने की धमकी देती थी। परिवार का आरोप था कि पूनम ने तुषार से करोड़ों रुपये वसूले और यहां तक कि उनके एक प्री-प्राइमरी स्कूल में जबरन 50 प्रतिशत हिस्सेदारी भी ले ली। परिवार का मानना था कि इसी मानसिक दबाव और ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर तुषार ने आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठाया। हालांकि, अब पूनम भदोरिया ने अदालत में पेश अपनी जमानत याचिका में इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए उल्टा गेलानी परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूनम के वकील ने अदालत में दलील दी कि तुषार की आत्महत्या के लिए पूनम जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि उनके अपने परिवार का व्यवहार उन्हें मानसिक रूप से तोड़ रहा था। याचिका में दावा किया गया कि तुषार का परिवार उन्हें एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि केवल एक आर्थिक संसाधन या 'एटीएम मशीन' के रूप में देखता था। पूनम की ओर से अदालत में पेश किए गए WhatsApp चैट ने इस मामले को और अधिक संवेदनशील बना दिया है।

कर्ज और प्रताड़ना ने छीना परिवार का सहारा, सूरत की मासूम बच्ची बनी दर्दनाक त्रासदी की जीवित गवाह

जीएनएस)। गुजरात के सूरत शहर में घटी एक हृदयविदारक घटना ने पूरे समाज को गहरे सदमे में डाल दिया है। वेसू इलाके के एक शांत और आधुनिक अपार्टमेंट में रहने वाले खेतान परिवार की जिंदगी 24 फरवरी की सुबह अचानक हमेशा के लिए समाप्त हो गई। इस दर्दनाक घटना में परिवार के तीन सदस्यों—पिता बालमुकुंद खेतान, मां प्रियंका खेतान और उनकी 9 वर्षीय बेटी भाव्या—की मौत हो गई, जबकि 7 वर्षीय छोटी बेटी पार्थिवी चमत्कारिक रूप से बच गई। अब यह मासूम बच्ची न केवल अपने माता-पिता और बहन को खो चुकी है, बल्कि वह इस पूरे हादसे की सबसे महत्वपूर्ण गवाह भी बन गई है। बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन घर के अंदर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर परिवार एक गहरे मानसिक और आर्थिक संकट से गुजर रहा था। शुरुआती जांच में सामने आया है कि परिवार पर भारी कर्ज का दबाव था और वे लगातार मानसिक प्रताड़ना का सामना कर रहे थे। इसी दबाव के चलते माता-पिता ने एक भयावह फैसला लिया, जिसने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें आर्थिक परेशानी और कर्ज देने वाले व्यक्ति द्वारा कथित रूप से की जा रही प्रताड़ना का जिक्र किया गया है।

घटना की शुरुआत उस समय हुई जब प्रियंका खेतान ने अपने पिता को फोन कर बताया कि उनके पति अचानक बेहोश हो गए हैं और उनकी हालत गंभीर है। यह सुनकर परिवार के सदस्य तुरंत उनके घर पहुंचे। जब वे वहां पहुंचे, तो उन्हें घर के अंदर का दृश्य देखकर गहरा झटका

लगा। बालमुकुंद खेतान मृत अवस्था में पड़े थे, जबकि प्रियंका और उनकी बड़ी बेटी भाव्या अचेत अवस्था में थीं। छोटी बेटी पार्थिवी घर के बाहर थी और उसकी हालत भी बेहद खराब थी। वह लगातार उल्टी कर रही थी और बहुत कमजोर दिखाई दे रही थी।

परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों ने तुरंत सभी को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद बालमुकुंद को बचाया नहीं जा सका। अगले दिन प्रियंका और भाव्या ने भी दम तोड़ दिया। केवल पार्थिवी ही जीवित बच पाई, जिसका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार, पार्थिवी की जान इसलिए बच गई क्योंकि जहर पीने के बाद उसे उल्टी हो गई, जिससे जहर का असर पूरी तरह उसके शरीर में नहीं फैल पाया।

इस घटना के बाद पुलिस ने जब जांच शुरू की, तो उन्हें एक विस्तृत सुसाइड नोट मिला, जिसमें परिवार की आर्थिक परेशानियों का विस्तार से उल्लेख किया गया था। नोट में लिखा गया था कि कर्ज और लगातार मानसिक दबाव के कारण परिवार ने यह कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है, जो फिलहाल फरार बताया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही इस मामले की पूरी सच्चाई सामने आ सकेगी।

इस पूरी घटना का सबसे मार्मिक पहलू छोटी बच्ची पार्थिवी की स्थिति है। जब वह धीरे-धीरे होश में आई, तो उसने जो बातें बताईं, वे बेहद भावुक और दिल दहला देने वाली थीं। मासूम बच्ची ने बताया कि घटना से पहले उसके माता-पिता एक नोटबुक में कुछ लिख रहे थे। उसने यह भी बताया कि उसकी मां ने उसे और उसकी बहन को कुछ पीने के लिए दिया था, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। इन मासूम शब्दों में छिपा दर्द और अनजानी सच्चाई इस त्रासदी की भयावहता को और गहरा कर देती है।

अब पार्थिवी अपने माता-पिता और बहन के बिना अकेली रह गई है। उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है, जहां उसे अपने जीवन की शुरुआत फिर से करनी होगी, लेकिन उसके दिल और दिमाग में उस दिन की यादें हमेशा के लिए अंकित हो चुकी हैं। परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों ने बच्ची की देखभाल की जिम्मेदारी संभाली है, लेकिन माता-पिता के प्यार और सुरक्षा की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता।

यह घटना केवल एक परिवार की व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी भी है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आर्थिक दबाव, मानसिक तनाव और सामाजिक परिस्थितियां किस तरह लोगों को ऐसे कठोर फैसले लेने के लिए मजबूर कर सकती हैं। यह भी स्पष्ट होता है कि ऐसे लोगों को समय रहते भावनात्मक और सामाजिक समर्थन मिलना कितना आवश्यक है।

पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपी की तलाश जारी है। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि दोषी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। इस घटना ने पूरे इलाके में शोक और संवेदना का माहौल बना दिया है। लोग इस बात से स्तब्ध हैं कि एक सामान्य दिखने वाला परिवार अंदर ही अंदर इतनी बड़ी पीड़ा से गुजर रहा था।

आज पार्थिवी की मासूम आंखों में अपने माता-पिता और बहन की यादें हैं। वह शायद अभी पूरी तरह समझ नहीं पाई है कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी है। यह घटना समाज को यह याद दिलाती है कि हर व्यक्ति की मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को समझना जरूरी है और जरूरत के समय सहायता और सहानुभूति देना ही मानवता का सबसे बड़ा धर्म है।

संपादकीय

रिश्तों में छल

हाल ही में सामने आए एक सर्वेक्षण में, यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि जीवन साथी की निगरानी के लिये बड़ी संख्या में डिटेक्टिव एजेंसियों की मदद ली जा रही है। तमाम विवाहेत्तर संबंधों की पड़ताल से बड़ी संख्या में शक सही निकल रहे हैं। हालांकि, इस सर्वे के दायरे और उसकी विश्वसनीयता की कसौटी के प्रश्न सामने हैं, लेकिन यह एक कड़वी हकीकत है कि हमारी पारिवारिक संस्था में अविश्वास की सेंध लग रही है। खाओ-पियो मौज करो की पश्चिमी संस्कृति के अंधानुकरण से वैवाहिक संस्था की शुचिता को आंच आई है। समाज में अलगाव, तलाक व हिंसक प्रतिशोध के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। रही सही कसर कथित सोशल मीडिया ने पूरी कर दी है, जिसने हमारे समाज में वर्जित माने जाने वाले भदेस विषयों को न्यू नॉर्मल बना दिया है। दरअसल, हाल के वर्षों में भारतीय समाज तेजी से संक्रमणकालीन दौर में जा पहुंचा है। कभी जिस रिश्ते को सिरे चढ़ाते वक्त जन्म-जन्मांतर साथ निभाने का वायदा किया जाता था, आज उसी जीवन साथी की निगरानी के लिये डिटेक्टिव एजेंसियों की मदद ली जा रही है। यह दुखद ही है कि जिन जीवन मूल्यों, संयम व शुचिता के रिश्तों के लिये भारत दुनिया में जाना जाता था, वहां आज यौन स्वच्छंदता व विवाहेत्तर संबंधों का दायरा बढ़ रहा है। एक समय था कि भारतीय संयुक्त परिवार की छांव में संयमित व मर्यादित व्यवहार करते थे। बड़ों का अनुशासन मर्यादा की रक्षा करता था। कामकाज का स्वरूप और स्थानीय रोजगार भी जीवन व्यवहार को संतुलित व संयमित करते थे। लेकिन हमारी कार्य संस्कृति में बदलाव व देश-विदेश में कामकाज के लिये बाहर जाने के बाद व्यक्ति स्वच्छंद व्यवहार करने लगा। यही वजह है कि विदेश में रहने वाले पति या पत्नी के व्यवहार की पड़ताल के लिये डिटेक्टिव एजेंसियों की मदद लेने के मामले लगातार उजागर हुए हैं। जिसके बाद मुकदमेबाजी, अलगाव व टकराव की खबरें सामने आने लगती हैं।

दरअसल, विगत में भारतीय समाज में व्यक्ति के सार्वजनिक व्यवहार को संयुक्त परिवार व समाज संयमित करता था। लेकिन धीरे-धीरे आर्थिक आत्मनिर्भरता के बाद लोगों ने बड़े-बुजर्गों व समाज के हस्तक्षेप को अस्वीकार करना शुरू कर दिया। विगत में हमारी फिल्मों व टीवी निर्माताओं ने दर्शकों की भीड़ जुटाने के लिये हमेशा असामान्य वैवाहिक रिश्तों को अपनी कथावस्तु बनाया। इन असामान्य रिश्तों को इस ग्लैमर के साथ पेश किया जाता रहा है कि कालांतर उसका प्रभाव समाज पर नजर आने लगा। आज तो विदेशी धरती से संचालित इंटरनेट व सोशल मीडिया ने तो असामान्य रिश्तों की पराकाष्ठा दर्शा दी। विडंबना यह रही है कि मीडिया ने भी ऐसी नकारात्मक प्रवृत्तियों को इतनी तरजीह दी कि समाज के एक तबके में असामान्य रिश्तों को सामान्य माना जाने लगा। एक हकीकत यह भी है कि देश पर तमाम विदेशी आक्रांताओं ने भारतीय संस्कृति को इतनी क्षति नहीं पहुंचाई होगी, जितनी इंटरनेट व सोशल मीडिया के माध्यम से परोसी जा रही अपसंस्कृति ने विकृतियां पैदा की। नई पीढ़ी ही नहीं, उम्र दराज लोग भी कामदेव के मोहपाश में बंधे वर्जनाओं को लांघने लगे हैं। सोशल मीडिया पर बालाओं के मोहपाश में बंधकर गांठ का धन गंवाने वालों में बुजुर्गों की संख्या भी कम नहीं है। निस्संदेह, विवाह एक पवित्र बंधन है। जिसका निर्वहन संयम, सहजता, सहयोग, धैर्य और त्याग से ही होता है। लगता है कहीं न कहीं नई पीढ़ी लगातार धैर्य खोती जा रही है। रिश्तों के दीर्घकालिक निर्वहन का मूलमंत्र यही है कि हम जीवन-साथी की छोटी-मोटी कमियों को नजरअंदाज करके सामंजस्य के साथ जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाएं। असामान्य रिश्तों का अल्पकालिक सुख भले ही लुभाता हो, मगर उसकी कीमत परिवार को लंबे समय तक चुकानी पड़ती है। जिसका नकारात्मक प्रभाव बच्चों के मन-मस्तिष्क पर भी घातक होता है। यह भी एक हकीकत है कि जब परिवार के विवाद घर की दहलीज लांघते हैं, तो इससे लाभ उठाने वाले पेशेवरों की पूरी बिरादरी मुस्तैद खड़ी होती है। निश्चित ही रिश्तों में छल की प्रवृत्ति भारत में मूल्यों वाली विवाह संस्था के लिये एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इसका मुकाबला संयम, सहयोग, त्याग व समर्पण जैसे जीवन मूल्यों से ही संभव है। इसका समाधान कोर्ट-कचहरियों में नहीं मिलेगा।

इस्राइल से दोस्ती और गहरी करने का उपक्रम

> सवाल है, भारत को हेक्सागन समझौते में शामिल होना चाहिए, या नहीं? निर्गुट आंदोलन के फ़ाउंडिंग मेंबर होने के नाते, नई दिल्ली ने हमेशा से कट्टर गुट की पॉलिटिक्स से परहेज किया है।

नवंबर, 2025 में, भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इस्राइल का दौरा किया था और भारत- इस्राइल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए स्ट्रक्चर्ड बातचीत शुरू करने के लिए टर्म्स ऑफ़ रेफ़रेंस पर साइन किए। वाणिज्य मंत्री के इस दौरे के दौरान 250 से ज़्यादा बी-टू-बी मीटिंग हुईं, साथ ही दोनों तरफ़ के बिज़नेस और सरकारी नेताओं को एक साथ लाने वाले फ़ोरम भी हुए। लेकिन ऐसा कुछ तय नहीं हुआ था कि भारत 'हेक्सागन अलायंस' का हिस्सा बनेगा। पीएम मोदी का दो दिवसीय इस्राइल दौरा 26 फ़रवरी, 2026 को समाप्त हो जायेगा। पूरी दुनिया की नज़र व्यापार से अधिक हेक्सागन समझौते पर है।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी थी, कि मोदी और उनके समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू भारत-इस्राइल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे और सुरक्षा, साइंस-टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एग्रीकल्चर, वॉटर मैनेजमेंट, ट्रेड, इकॉनमी और लोगों के बीच उभयपक्षीय संबंधों पर अगले कदमों पर चर्चा करेंगे। स्टॉकहोम स्थित 'सीपरी' ने 2025 में रिपोर्ट दी थी, कि इस्राइल 2020-24 में दुनिया का आठवां सबसे बड़ा हथियार एक्सपोर्टर था, और भारत इस्राइली हथियारों का सबसे बड़ा अकेला इंपोर्टर था, जो उस समय में इस्राइली एक्सपोर्ट का 34 प्रतिशत था। यह 34 प्रतिशत अब और कितना प्लस होता है, वह नए समझौते से स्पष्ट हो जायेगा।

नेतन्याहू ने कहा, 'मेरे सामने जो विज़न है, उसके हिसाब से हम एक पूरा सिस्टम बनाएंगे। हेक्सागन ऑफ़ अलायंस का मकसद ऐसे देशों की एक धुरी बनाना है, जो मुस्लिम कट्टरपंथी गुटों के खिलाफ एक जैसी राय रखते हों। एक नहीं दोनों कट्टरपंथी गुट। पहला, ईरान की सरपरस्ती वाली शिया धुरी, जिस पर हमने बहुत ज़ोरदार हमला किया है। और दूसरी, उभरती हुई कट्टरपंथी सुन्नी धुरी।'

हालांकि, किसी भी सरकार ने इस प्लान, या इसके सांप्रदायिक ढांचे का खुले तौर पर समर्थन नहीं किया है। नेतन्याहू की ख्वाहिश है कि इस समूह में भारत, इस्राइल, ग्रीस, साइप्रस और कुछ उदारवादी अरब व अफ्रीकी देश शामिल हों। यह दीगर है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (आईसीसी) इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके विदेश मंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की तैयारी में है। नेतन्याहू ने जिन तीन देशों का नाम लिया, उनमें से ग्रीस और साइप्रस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य हैं। 'आईसीसी' में जो कुछ पक रहा है, उसे काउंटर करने के वास्ते जो कुछ तैयारी नेतन्याहू की है, वो समझ में आने लगा है।

किंग्स कॉलेज लंदन में सिक्योरिटी स्टडीज़ के एसोसिएट प्रोफेसर एंड्रियास क्रेग कमेंट करते हैं, कि इस्राइली प्रधानमंत्री शायद अपने आइडिया को बढ़ा-चढ़ाकर बता रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 'हेक्सागन अलायंस' नाटो स्टाइल के समझौते जैसा हो। नेतन्याहू 'शिया एक्सिस', जिसे 'एक्सिस ऑफ़ रेज़िस्टेंस' भी कहा जाता है, के खिलाफ अपनी 'जीत' को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। यह मध्य-पूर्व में इस्राइली और पश्चिमी असर का विरोध करने वाले ईरान केंद्रित नेटवर्क है। लेबनान में हिज़्बुल्ला को ईरान सपोर्ट करता है, जिसे लंबे समय से इस इलाके का सबसे ताकतवर नॉन-स्टेट एक्टर माना जाता है। 2024 में इस्राइल द्वारा ज़्यादातर लीडरशिप को खत्म करने से पहले हिज़्बुल्ला तेहरान के साथ जुड़ा हुआ था। इराक में तेहरान कई शिया हथियारबंद समूहों के साथ रिश्ते बनाए हुए है, जिसमें कताइब हिज़्बुल्ला जैसे ग्रुप शामिल हैं। हाल ही में, यमन में, हूथी, एक ज़ैदी शिया आंदोलन, खास तौर पर उभरा है, जिसे तेहरान ने अधोसंरचनात्मक सहयोग, ट्रेनिंग और हथियार दिए हैं। इसके बर'अक्स, सुन्नी अतिवादी समूह है। इस्राइल ने 2025 में इस इलाके के कम से कम 6 सुन्नी बहुल देशों पर हमला किया, जिसमें फ़लस्तीन, लेबनान, सीरिया और यमन शामिल हैं। गाज़ा से जुड़े ट्यूनीशिया और ग्रीस के इलाके में भी हमले किए। इस्राइल ने मिस्र, तुर्की, सऊदी अरब, इराक और जॉर्डन को भी धमकी दी है।

इस इलाके के कई सुन्नी-बहुल देशों ने इस्राइल के इलाके में लड़ाई के जवाब में कूटनीतिक तरीके से कोऑर्डिनेट किया है। इस्राइल ने 26 दिसंबर, 2025 को सोमालीलैंड को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है। उस फैसले ने अरब लीग, खाड़ी सहयोग परिषद, अफ्रीकी यूनियन और इस्लामी सहयोग संगठन (ओआईसी) देशों के बाद अब चीन को भी इस्राइल के खिलाफ खड़ा कर दिया है। सोमालीलैंड, लाल सागर और बाब अल-मंडेब के पास होने की वजह से 'हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका' का सामरिक इलाका है, जिसने 1991 में गृहयुद्ध के दौरान सोमालिया से अलग होकर खुद को स्वतंत्र देश घोषित कर लिया था।

सवाल है, भारत को हेक्सागन समझौते में शामिल होना चाहिए, या नहीं? निर्गुट आंदोलन के फ़ाउंडिंग मेंबर होने के नाते, नई दिल्ली ने हमेशा से कट्टर गुट की पॉलिटिक्स से परहेज किया है। भारत एक ही समय में चीन, रूस और अमेरिका के साथ जुड़ा रहता है। भारत के खाड़ी देशों में भी बड़े अच्छे रिश्ते हैं। नई दिल्ली के ईरान के साथ करीबी रिश्ते हैं, वह इन रिश्तों को 'सिविलाइज़ेशनल' बताता है। साथ ही भारत, सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन भी बढ़ा रहा है। अभी यह पता नहीं है कि कौन से अरब और अफ्रीकी देश नेतन्याहू के सोचे हुए 'हेक्सागन ऑफ़ अलायंस' का हिस्सा बनेंगे। इस बीच इस्राइली प्रेसिडेंट आइज़ैक हर्ज़ोग मंगलवार को इथियोपिया पहुंचे। मकसद हेक्सागन ऑफ़ अलायंस का हिस्सा बनने के वास्ते इथियोपिया को सहमत करना है।

इस्राइली राजनीतिक विश्लेषक ओरी गोल्डबर्ग ने कहा, 'सच तो यह है कि इस्राइल के पास हर तरह के टैक्टिकल, टेक्निकल पार्टनरशिप और अलायंस हो सकते हैं, लेकिन कोई भी इस्राइल को 10 फुट के डंडे से भी नहीं छूना चाहता। इस्राइली ब्रांड इतना खराब हो गया है कि इससे सिर्फ़ संभावित अराजकता और अस्थिरता ही आती है।' पोलिटिकल एनालिस्ट ओरी गोल्डबर्ग ने कहा, 'इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं, इसलिए नेतन्याहू के पास राजनेता की तरह काम करने और यह तर्क देने का एक साफ मौका है कि इस्राइल डिप्लोमैटिक रूप से अलग-थलग नहीं है और वह अभी भी सार्थक क्षेत्रीय और क्षेत्रीय-बाहरी पार्टनरशिप कर सकता है।

मोदी ऐसे समय तेल अवीव पहुंचे हैं, जब वहां घरेलू राजनीतिक अंतर्विरोध चरम पर है। पीएम मोदी द्वारा इस्राइली संसद 'नेसेट' को सम्बोधित करना था। संसद के स्पीकर आमिर ओहाना ने सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट यित्ज़ाक अमित को बुलाने से मना कर दिया, इससे भड़के विपक्ष के नेता यायर लैपिड ने नेसेट सत्र के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। 2016 से नेतन्याहू के खिलाफ रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और विश्वासघात के आरोपों वाले तीन मामलों में मुकदमा भी चल रहा है, जिसमें उन्हें जेल भी हो सकती है। अदालत से नेतन्याहू के छत्तीस के आकड़े हैं!

प्रेरणा

गुरु की दिव्य कृपा से साधारण बालक का संगीत सम्राट बनने का अद्भुत सफर

भारत की पवित्र भूमि पर सदियों से गुरु और शिष्य की परंपरा केवल ज्ञान देने का माध्यम नहीं रही, बल्कि आत्मा को जागृत करने और जीवन को दिव्यता से जोड़ने का मार्ग रही है। ऐसी ही एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा है उस बालक की, जो अपनी शरारतों और स्वाभाविक प्रतिभा के कारण गुरु की दृष्टि में आया और आगे चलकर भारतीय संगीत का अमर नक्षत्र बना। यह कथा है महान संगीत सम्राट तानसेन और उनके परम पूज्य गुरु स्वामी हरिदास की, जिनकी कृपा ने एक साधारण बालक को असाधारण बना दिया।

बहुत समय पहले, मध्य भारत के ग्वालियर के पास स्थित बेहट नामक छोटे से गांव में एक बालक रहता था, जिसका नाम तन्ना था। तन्ना अत्यंत चंचल, नटखट और साहसी था। उसे जंगलों में घूमना, पशु-पक्षियों की आवाज़ों की नकल करना और लोगों को चौंकाना बहुत पसंद था। उसकी यह आदत केवल शरारत नहीं थी, बल्कि उसके भीतर छिपी एक असाधारण ध्वनि प्रतिभा का संकेत थी, जिसे उस समय कोई समझ नहीं पाया था। एक दिन की बात है, जब वृन्दावन के महान संत और संगीतज्ञ स्वामी हरिदास अपनी शिष्यमंडली के साथ यात्रा करते हुए बेहट गांव के पास एक इमली के बाग़ से गुजर रहे थे। वातावरण शांत था, पेड़ों के बीच से हवा धीरे-धीरे बह रही थी, और सभी शिष्य अपने गुरु के साथ ध्यान और भक्ति में लीन होकर चल रहे थे। तभी अचानक एक भयानक शेर की दहाड़ पूरे बाग़ में गूंज उठी। वह आवाज़ इतनी वास्तविक और भयावह थी कि सभी शिष्य भय से कांप उठे। कुछ के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी, और कुछ ने तो भागने की भी कोशिश की।

लेकिन स्वामी हरिदास जी केवल एक संत ही नहीं, बल्कि एक गहन ज्ञानी और सूक्ष्म दृष्टि वाले महापुरुष थे। उन्हें तुरंत आभास हो गया कि इस स्थान पर शेर का होना संभव नहीं है। उन्होंने अपने शिष्यों को शांत रहने का संकेत दिया और स्वयं उस दिशा में बढ़े, जहां से आवाज़ आई थी। जब उन्होंने पेड़ों के पीछे जाकर देखा, तो उन्हें एक छोटा बालक दिखाई दिया, जो फिर से शेर की तरह दहाड़ने का प्रयास कर रहा था। वह बालक कोई और नहीं, बल्कि तन्ना था।

स्वामी जी ने बालक को ध्यान से देखा। उन्होंने उससे प्रेमपूर्वक पूछा, "क्या तुम अन्य पशु-पक्षियों की आवाज़ भी निकाल सकते हो?" तन्ना ने मुस्कुराते हुए तुरंत कोयल, गाय, बकरी, और कई अन्य पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें इतनी सटीकता से निकालकर सुनाईं कि स्वामी जी आश्चर्यचकित रह गए। यह कोई साधारण कौशल नहीं था। यह एक जन्मजात प्रतिभा थी, जिसे केवल उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। स्वामी हरिदास जी ने तुरंत समझ लिया कि यह बालक ईश्वर का विशेष वरदान लेकर आया है। उन्होंने बालक के पिता से मिलकर उनसे विनम्रता से अनुरोध किया कि वे तन्ना को अपने साथ वृन्दावन ले जाना चाहते हैं, ताकि उसे संगीत की शिक्षा दी जा सके। प्रारंभ में पिता को संकोच हुआ, क्योंकि वे अपने पुत्र से दूर नहीं होना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने स्वामी जी की महानता और उनके उद्देश्य को समझा, तो उन्होंने सहर्ष अनुमति दे दी।

इस प्रकार तन्ना का जीवन एक नए मार्ग पर चल पड़ा। वृन्दावन में स्वामी हरिदास जी के सान्निध्य में उसने केवल संगीत ही नहीं सीखा, बल्कि अनुशासन, साधना, भक्ति और आत्मसंयम का महत्व भी समझा। संगीत उसके लिए केवल स्वर और लय का खेल नहीं रहा, बल्कि ईश्वर तक पहुंचने का एक माध्यम बन गया। स्वामी जी ने उसे सिखाया कि सच्चा संगीत वही है, जो हृदय से निकलकर आत्मा को स्पर्श करे।

तन्ना ने पूरे समर्पण और श्रद्धा के साथ अपने गुरु की सेवा की। वह प्रतिदिन घंटों तक रियाज़ करता, अपने स्वरों को शुद्ध करता और अपने भीतर की भावनाओं को संगीत के माध्यम से व्यक्त करना सीखता। धीरे-धीरे उसकी आवाज़ में एक अद्भुत शक्ति और माधुर्य आ गया। उसकी गायकी में ऐसा प्रभाव था कि उसे सुनने वाला व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता था।

लगभग दस वर्षों की कठिन साधना और गुरु की कृपा से तन्ना एक महान गायक बन गया। अब वह केवल एक शरारती बालक नहीं रहा, बल्कि एक सिद्ध संगीतज्ञ बन चुका था। उसकी प्रतिभा और समर्पण को देखकर स्वामी हरिदास जी ने उसे नया नाम दिया — तानसेन। यह नाम उसके नए जीवन और उसकी महानता का प्रतीक था। समय के साथ तानसेन की ख्याति दूर-दूर तक फैलने लगी। उसकी आवाज़ में इतनी शक्ति थी कि कहा जाता है, वह दीपक राग गाकर दीपक जला सकता था और मेघ मल्हार गाकर वर्षा करा सकता था। उसकी गायकी केवल मनोरंजन नहीं थी, बल्कि प्रकृति और ब्रह्मांड से संवाद करने का एक माध्यम थी।

आखिरकार उसकी ख्याति मुगल सम्राट अकबर तक पहुंची, जो स्वयं कला और संगीत के महान संरक्षक थे। अकबर ने तानसेन को अपने दरबार में आमंत्रित किया और उन्हें नवरत्नों में स्थान दिया। यह केवल तानसेन की प्रतिभा का सम्मान नहीं था, बल्कि उनके गुरु स्वामी हरिदास की शिक्षा और कृपा का भी सम्मान था।

तानसेन ने अपने जीवन में कभी भी अपने गुरु को नहीं भुलाया। वे हमेशा कहते थे कि जो कुछ भी उन्होंने प्राप्त किया है, वह केवल अपने गुरु की कृपा से ही संभव हुआ है। उनका मानना था कि गुरु ही वह दीपक हैं, जो शिष्य के जीवन के अंधकार को दूर करके उसे प्रकाश की ओर ले जाते हैं।

यह कथा हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति के भीतर एक विशेष प्रतिभा छिपी होती है, लेकिन उसे पहचानने और निखारने के लिए एक सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु केवल ज्ञान नहीं देते, बल्कि जीवन को दिशा देते हैं। यदि तन्ना को स्वामी हरिदास जैसे गुरु नहीं मिले होते, तो शायद वह केवल एक साधारण बालक बनकर रह जाता। लेकिन गुरु की कृपा ने उसे अमर बना दिया।

आज भी तानसेन का नाम भारतीय संगीत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। उनकी गायकी, उनकी साधना और उनके गुरु के प्रति उनकी श्रद्धा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल प्रतिभा से नहीं, बल्कि गुरु के मार्गदर्शन, समर्पण, और निरंतर साधना से प्राप्त होती है। गुरु की कृपा से ही साधारण व्यक्ति असाधारण बनता है, और यही इस अमर कथा का सबसे बड़ा संदेश है।

अपने मूल उद्देश्य से भटक गया रेरा

जब भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 यानी रेरा के नौ साल पूरे हो चुके हैं, तब पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की ओर से उसके खिलाफ की गई सख्त टिप्पणी ने सबका ध्यान खींचा। इस कानून को इस उम्मीद में बनाया गया था कि इससे घर-फ्लैट खरीदारों को मदद मिलेगी और उन्हें बिल्डरों की मनमानी और भ्रष्टाचार से राहत मिलेगी, लेकिन हो रहा उलटा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेरा को बंद कर देना ही बेहतर है, क्योंकि यह डिफाल्टर बिल्डरों को फायदा पहुंचा रहा है और रिटायर्ड आइएएस अधिकारियों का पुनर्वास केंद्र बन गया है। अब समय आ गया है कि राज्य सरकारें रेरा के गठन पर दोबारा विचार करें। संसद ने रेरा इसलिए बनाया था, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर में अनुशासन, पारदर्शिता आए और लोगों का भरोसा बने। उपभोक्ता कानून की तरह सिर्फ नुकसान होने के बाद मुआवजा देना इसका उद्देश्य नहीं था।

रेरा को इस तरह बनाया गया था कि वह नुकसान होने से पहले ही उसे रोके। यानी लगातार निगरानी और सख्त कार्रवाई इसकी असली ताकत थी। सवाल यह है कि क्या इसे सही तरीके से लागू किया गया? अगर रेरा के प्रविधानों को सख्ती से लागू किया जाता और पंजीकरण के समय बिल्डरों की पूरी और गंभीर जांच होती तो अधिकतर प्रोजेक्ट समय पर और बिना किसी शिकायत के पूरे होते। ऐसी स्थिति में बिल्डर समय पर प्रोजेक्ट पूरा करना अपनी प्रतिष्ठा का विषय बनाते। सही तरीके से लागू किया गया कानून सिर्फ सजा नहीं देता। वह ऐसी व्यवस्था बनाता है, जहां अच्छा प्रदर्शन दिखे भी और उसे मापा भी जा सके।

समय पर और बिना विवाद के प्रोजेक्ट पूरा होने पर ही "रेरा है तो भरोसा है" जैसे नारे सच में भरोसा पैदा करते, सिर्फ नारा बनकर नहीं रह जाते, लेकिन हकीकत यह है कि पंजीकरण सिर्फ कागज अपलोड करने की प्रक्रिया बनकर रह गई है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां बिल्डर के ब्रोशर में देशभर में कई परियोजनाएं दिखाई गईं, लेकिन रेरा पोर्टल पर केवल एक ही पंजीकृत परियोजना दर्ज थी और शिकायतों का डाटा भी बहुत कम था।

जब प्रोजेक्ट की सुविधाओं की जानकारी बिल्डर की वेबसाइट, स्वीकृत नक्शों और रेरा पोर्टल पर अलग-अलग दर्ज हो तो फिर कोई घर-खरीदार प्रोजेक्ट के बारे में सही और सटीक जानकारी कहां से हासिल करे? यदि जानकारी ही स्पष्ट न हो तो रेरा के वेब पोर्टल का घर-खरीदार को वास्तविक लाभ क्या मिला? बिक्री समझौते का मसौदा भी कई बार उपलब्ध नहीं होता, जिसे कानून के तहत अनिवार्य रूप से रेरा वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए। यह दिखाता है कि परियोजनाओं का पंजीकरण ठीक से नहीं किया जा रहा है और शुरुआत में ही सही जांच नहीं हो रही है।

रेरा कहता है कि प्रोजेक्ट की समय सीमा बढ़ाना सिर्फ खास परिस्थितियों में होना चाहिए, लेकिन कई राज्यों में एक्सटेंशन आम बात है। एक्सटेंशन मिलने के बाद भी सभी खरीदारों को अपने-आप मुआवजा मिलना शुरू नहीं होता। आम तौर पर देरी का कोई सीधा आर्थिक असर बिल्डर पर नहीं पड़ता, लेकिन घर-खरीदार के लिए देरी बहुत ही महंगी पड़ती है। कायदे से यह बिल्डर को भी महंगी पड़नी चाहिए। आज डाटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। प्राधिकरण चाहें तो निर्माण की वास्तविक प्रगति की तुलना रिपोर्ट से कर सकते हैं, पैसों के प्रवाह को देख सकते हैं, जोखिम पहले से पहचान सकते हैं और भविष्य में उत्पन्न होने वाले किसी भी विलंब या विवाद को पहले ही पकड़ सकते हैं और समय रहते सुधारात्मक कदम उठा सकते हैं, लेकिन इस रोकथाम पर उनका ध्यान ही नहीं है जो कानून का मुख्य उद्देश्य है।

महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (महारेरा) की वेबसाइट पर उपलब्ध एक बिक्री समझौते में लिखा है कि अगर खरीदार 15 दिनों में कब्जा नहीं लेता तो 40 रुपये प्रति वर्ग फुट प्रति माह होल्डिंग चार्ज देना होगा। 1,000 वर्ग फुट के फ्लैट पर यह 40,000 रुपये प्रति माह बनता है। कानून खरीदार को कब्जा लेने के लिए 60 दिन देता है। नियमों में भी कहा गया है कि देरी की स्थिति में मुख्यतः मेंटेनेंस चार्ज देय होगा। फिर भी ऐसे प्रविधान खुलेआम बिल्डरों द्वारा डाले जा रहे हैं। जब बिल्डर खुद देरी करता है तो खरीदार के लिए "अन-होल्डिंग चार्ज" जैसा कोई प्रविधान नहीं है, जबकि खरीदार को एक साथ ईएमआइ और किराया देना पड़ता है।

लगता है बिल्डर मानकर चल रहे हैं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी। कोई कानून तभी काम करता है, जब नियम तोड़ना महंगा हो। अगर नियम तोड़ना सस्ता पड़े तो अनुशासन खत्म हो जाता है। जब नियम मानना वैकल्पिक लगे और नियम तोड़ने पर कोई खास नुकसान न हो तो कानून अपना असर खो देता है। कोई भी मजबूत कानून अगर नरमी से लागू किया जाए तो वह असरदार नहीं होता। रेरा तभी सफल होगा, जब उसके प्राधिकरण अपनी मूल जिम्मेदारी पर लौटेंगे और कानून के प्रविधानों को सख्ती से लागू करके घर-खरीदारों की रक्षा करेंगे। रेरा ऐसी सख्त और सक्रिय कार्रवाई करे, जो अनुशासन स्थापित करे और देरी वाले प्रोजेक्ट समय पर पूरे कराए। रेरा को ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जहां शिकायत की नौबत ही न आए और तभी रेरा सफलता के नए आयाम लिख पाएगा। कानून मजबूत है। अब जरूरत है मजबूत इरादे की।

अभियान

माणिक्य रत्न की शक्ति और सावधानियां: सूर्य को मजबूत करने से पहले जान लें पूरी सच्चाई

वैदिक ज्योतिष में सूर्य को समस्त ग्रहों का राजा माना गया है। सूर्य केवल एक खगोलीय पिंड नहीं, बल्कि जीवन, आत्मा, ऊर्जा और चेतना का मूल स्रोत है। जिस प्रकार पृथ्वी पर समस्त जीवन सूर्य की रोशनी और ऊर्जा पर निर्भर करता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी सूर्य आत्मबल, आत्मविश्वास, सम्मान और सफलता का आधार होता है। ज्योतिष के अनुसार जब किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, तो वह व्यक्ति प्रभावशाली, आत्मनिर्भर, नेतृत्व करने वाला और समाज में सम्मान प्राप्त करने वाला होता है। लेकिन जब सूर्य कमजोर, नीच या अशुभ प्रभाव में होता है, तो व्यक्ति को आत्मविश्वास की कमी, अपमान, असफलता, मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में सूर्य की शक्ति को बढ़ाने के लिए माणिक्य रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है।

माणिक्य, जिसे अंग्रेजी में रूबी कहा जाता है, लाल रंग का अत्यंत सुंदर और तेजस्वी रत्न होता है। यह लाल रंग सूर्य की अग्नि और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन काल से ही राजा, सम्राट और उच्च पदों पर आसीन लोग माणिक्य धारण करते रहे हैं, क्योंकि यह रत्न शक्ति, अधिकार और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार माणिक्य सीधे सूर्य ग्रह से जुड़ा हुआ है और इसे धारण करने से सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति के शरीर और आभामंडल में प्रवाहित होने लगती है।

जब किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर होता है, तो वह व्यक्ति अक्सर खुद को असुरक्षित महसूस करता है। उसे अपने निर्णयों पर विश्वास नहीं होता और वह दूसरों पर अधिक निर्भर रहता है। ऐसे लोग सार्वजनिक रूप से बोलने से डरते हैं, नेतृत्व की जिम्मेदारी लेने से बचते हैं और जीवन में आगे बढ़ने के अवसर खो देते हैं। माणिक्य धारण करने से व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास और साहस का संचार होता है। धीरे-धीरे व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने लगता है और उसके व्यक्तित्व में एक नई चमक दिखाई देने लगती है।

ज्योतिष में सूर्य को पिता का कारक ग्रह भी माना गया है। यदि सूर्य कमजोर हो, तो पिता के साथ संबंधों में तनाव, मतभेद या दूरी हो सकती है। माणिक्य धारण करने से इन संबंधों में सुधार होने की संभावना बढ़ती है। व्यक्ति अपने पिता के साथ बेहतर सामंजस्य स्थापित कर पाता है और पारिवारिक सम्मान में वृद्धि होती है। इसके अलावा सूर्य सरकारी पद, प्रशासन और अधिकार का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जो लोग प्रशासनिक सेवाओं, राजनीति, सेना या किसी भी नेतृत्व वाले क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए माणिक्य अत्यंत लाभकारी माना जाता है।

माणिक्य का प्रभाव केवल मानसिक और सामाजिक स्तर तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि इसका प्रभाव शारीरिक स्तर पर भी देखा जाता है। सूर्य हृदय, आंखों और रक्त संचार से संबंधित होता है। जब सूर्य कमजोर होता है, तो व्यक्ति को हृदय की कमजोरी, आंखों की समस्या या थकान जैसी परेशानियां हो सकती हैं। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार माणिक्य धारण करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और व्यक्ति अधिक सक्रिय और स्वस्थ महसूस करता है। उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और वह जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक आत्मविश्वास के साथ कर पाता है।

लेकिन माणिक्य जितना शक्तिशाली है, उतना ही संवेदनशील भी है। इसे बिना उचित ज्योतिषीय परामर्श के धारण करना नुकसानदायक हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य पहले से ही अत्यधिक प्रबल हो या अशुभ स्थिति में हो, तो माणिक्य धारण करने से नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। व्यक्ति को सिरदर्द, आंखों में जलन, क्रोध, अहंकार या मानसिक अशांति का अनुभव हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि माणिक्य धारण करने से पहले कुंडली का गहन विश्लेषण किया जाए।

रत्नों की आपसी संगति का भी विशेष महत्व होता है। सूर्य और शनि एक-दूसरे के शत्रु माने जाते हैं, इसलिए माणिक्य को नीलम के साथ नहीं पहनना चाहिए। इसी प्रकार सूर्य और राहु के बीच भी विरोध होता है, इसलिए गोमेद के साथ माणिक्य धारण करने से बचना चाहिए। सूर्य और शुक्र के संबंध भी अनुकूल नहीं माने जाते, इसलिए हीरे के साथ माणिक्य पहनना उचित नहीं होता। यदि इन नियमों की अनदेखी की जाए, तो व्यक्ति को मानसिक तनाव, भ्रम और जीवन में अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है।

माणिक्य धारण करने के लिए उसकी गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। रत्न प्राकृतिक, चमकदार और दोषरहित होना चाहिए। नकली या टूटा हुआ रत्न नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। इसे सोने या तांबे की अंगूठी में जड़वाना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये धातुएं सूर्य की ऊर्जा के साथ सामंजस्य स्थापित करती हैं।

माणिक्य को धारण करने का सबसे शुभ दिन रविवार माना जाता है, क्योंकि यह दिन सूर्य को समर्पित होता है। इसे सूर्योदय के समय धारण करना चाहिए। धारण करने से पहले अंगूठी को गंगाजल, कच्चे दूध और शुद्ध जल से शुद्ध करना चाहिए। इसके बाद सूर्य मंत्र का जाप करके अंगूठी को ऊर्जित किया जाता है। सामान्यतः "ॐ सूर्याय नमः" मंत्र का जाप किया जाता है। इसके बाद इसे दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में धारण किया जाता है।

माणिक्य धारण करने के बाद व्यक्ति के जीवन में धीरे-धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है और समाज में उसका सम्मान बढ़ता है। वह अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक गंभीर और समर्पित हो जाता है। लेकिन यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति अपने कर्म और व्यवहार को भी सकारात्मक बनाए। केवल रत्न धारण करने से ही सफलता नहीं मिलती, बल्कि परिश्रम, अनुशासन और ईमानदारी भी आवश्यक होती है।

आध्यात्मिक दृष्टि से माणिक्य आत्मा की शक्ति को जागृत करने वाला रत्न माना जाता है। यह व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में सहायता करता है। व्यक्ति के भीतर आत्मज्ञान और आत्मविश्वास का विकास होता है। वह अपने जीवन में स्पष्ट दिशा प्राप्त करता है और भ्रम की स्थिति से बाहर निकलता है। अंततः माणिक्य केवल एक आभूषण नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली ज्योतिषीय उपाय है। यह सूर्य की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है और व्यक्ति के जीवन में प्रकाश, शक्ति और सम्मान लाने की क्षमता रखता है। लेकिन इसे धारण करने से पहले सभी नियमों और सावधानियों का पालन करना आवश्यक है। सही परामर्श, सही विधि और सही समय पर धारण किया गया माणिक्य व्यक्ति के जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकता है और उसे सफलता, सम्मान और आत्मविश्वास प्रदान कर सकता है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

मोबाइल के दुरुपयोग के माध्यम से प्यार और ब्लैकमेल की खतरनाक सच्चाई

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। आज के आधुनिक युग में मोबाइल फोन एक आवश्यकता बन गए हैं, यहाँ तक कि इनका उपयोग पहले से कहीं अधिक हो रहा है, क्योंकि अब मोबाइल फोन के कैमरे से बेहतरीन तस्वीरें और वीडियो लिए जा सकते हैं। इसी तरह, इनका इस्तेमाल ब्लैकमेल करने के लिए भी किया जा सकता है। मोबाइल फोन स्वयं कोई अपराध नहीं करते, लेकिन आपराधिक गतिविधियों में इनका उपयोग बढ़ गया है। शादी से पहले प्रेमी जोड़े अपने निजी पलों के वीडियो मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड करने की हिम्मत करते हैं। वे प्रेमी जोड़े निजी पलों का आनंद लेते हुए वीडियो रिकॉर्ड करने का सुख जानते हैं। लेकिन ऐसा करके वे एक बड़ा और गलत जोखिम उठाते हैं।

शून्य त्रुटि एजेंसी

मान लीजिए कि प्रेमिका को वीडियो बनाने में आनंद आता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वह इसके लिए क्यों राजी हुई। यदि कोई अपने शरीर को दिखाने में संकोच करता है, तो प्रेमिका द्वारा वीडियो बनाने के लिए अपने शरीर को दिखाने पर प्रेम का महत्व अकल्पनीय रूप से बढ़ जाता है। क्या किसी को यह नहीं लगता कि प्रेमिका इस वीडियो का दुरुपयोग भी कर सकती है?

और अखबारों में ऐसी कितनी घटनाएं छपी हैं? फिर प्रेमी अपने साथी को ऐसे वीडियो डाउनलोड करने की इजाज़त क्यों देता है, जबकि उसे आनंद से देखने के बाद वीडियो डिलीट करने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है? यह किसी से छिपा नहीं है कि वीडियो डाउनलोड करने वाला प्रेमी विकृत आनंद लेता है और लोगों को सच्चे प्यार का एहसास दिलाता है या वह पोर्न फिल्म डाउनलोड करता है और किस उद्देश्य से करता है। और यह अज्ञानता नहीं है, शायद प्रेमी उस समय इसका विरोध भी करे। लेकिन अगर प्रेमी को इस पर विश्वास नहीं है, तो दृढ़ता से विरोध करने के बजाय, उसे इस पर विश्वास करना ही होगा। यही प्रेमी का स्वभाव है। क्या वह प्रेमी जो मानता है कि वह बलात्कारी नहीं है, अपने साथी के मन के बारे में थोड़ा भी जान सकता है? और अगर प्रेमी का इरादा बुरा है, तो अंत में प्रेमी के पास अपने फैसले पर पछताने के अलावा कोई चारा नहीं बचता।

जब कोई प्रेमी निजी पलों का वीडियो रिकॉर्ड करता है, तो प्रेमी को इसका कड़ा विरोध करना चाहिए। क्योंकि वहां कोई और मौजूद नहीं होता। अगर इस बुराई को रोका जाए, तो कई प्रेमी न केवल ब्लैकमेल होने से बचेंगे, बल्कि शीघ्रपतन के कारण आत्महत्या करने से भी बचेंगे । अब ऐसा लगता है किनिजी पलों की रिकॉर्डिंग पर तत्कालप्रतिबंध लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है ?

साबरमती स्टेशन पर रिडवलपमेंट कार्य के संबंध में ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित

जीएनएस)। अहमदाबाद मंडल के साबरमती स्टेशन पर रिडवलपमेंट कार्य के संबंध में प्लेटफॉर्म नं. 01 पर इंजीनियरिंग कार्य हेतु 27-28 फरवरी 2026 को ब्लॉक लिया गया है। जिसके कारण कुछ पैसेंजर ट्रेनें प्रभावित रहेगी। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः

आंशिक निरस्त ट्रेन

27 फरवरी 2026 की ट्रेन संख्या 14821 जोधपुर-साबरमती एक्सप्रेस आबूरोड-साबरमती के बीच आंशिक रद्द रहेगी।

28 फरवरी 2026 की ट्रेन संख्या 14822 साबरमती-जोधपुर एक्सप्रेस साबरमती-आबूरोड के बीच आंशिक रद्द रहेगी।

पूर्णतः निरस्त ट्रेनें

27 फरवरी 2026 की ट्रेन संख्या 79435/79436 साबरमती-पाटन-साबरमती डेमू रद्द रहेगी।

27 फरवरी 2026 की ट्रेन संख्या 69249/69250 साबरमती-कटोसन रोड-साबरमती मेमू रद्द रहेगी।

ट्रेनों के ठहराव, मार्ग और संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.inपर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

आधुनिकता की पटरी पर भीलड़ी: पुनर्विकास का 90% कार्य पूर्ण,अमृत भारत स्टेशन योजना से बदल रही स्टेशन की सूरत, लिफ्ट और दिव्यांग-अनुकूल सुविधाओं से होगा लैस

जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के भीलड़ी रेलवे स्टेशन का अमृत स्टेशन योजना के तहत लगभग 11.00 करोड़ की अनुमानित लागत से व्यापक पुनर्विकास किया जा रहा है। इस परियोजना का लगभग 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है। आधुनिक स्टेशन भवनः स्टेशन पर 18,223 वर्गफीट क्षेत्र में एक नया आधुनिक भवन बनाया जा रहा है, जिसमें अत्याधुनिक बुकिंग कार्यालय और वातानुकूलित व गैर-वातानुकूलित प्रतीक्षालय की सुविधा होगी। बेहतर कनेक्टिविटी और एप्रोचः यात्रियों की सुविधा के लिए 39,288 वर्गफीट लंबी एप्रोच रोड का सुधार व चौड़ीकरण किया गया है और 29,105 वर्गफीट क्षेत्र में सर्कुलेटिंग एरिया व पार्किंग का विकास किया जा चुका है। उन्नत प्रतीक्षालय और शौचालयः स्टेशन पर 1,582 वर्गफीट के प्रतीक्षालय का उन्नयन किया गया है और कुल 5 शौचालय ब्लॉकों में से 4 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

लिफ्ट और यात्री-अनुकूल सुविधाएं: सभी प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट की व्यवस्था की जा रही है तथा दिव्यांगजनों के लिए विशेष रैंप, पोर्च, सुगम प्रवेश/निकास द्वार और पृथक शौचालय व पार्किंग विकसित की गई है तथा यात्रियों को बैठने के लिए पर्याप्त संख्या में बेंचे भी लगाई गई है। पार्किंग और सौंदर्यीकरणः परिसर में चार पहिया, दो पहिया और ऑटो-रिक्शा के लिए अलग-अलग पार्किंग, प्लेटफॉर्म शेल्टर का विस्तार, हरित क्षेत्र का विकास और सौंदर्यीकरण का कार्य अंतिम चरण में है।

भविष्य की क्षमता का विस्तारः वर्तमान में भीलड़ी स्टेशन से प्रतिदिन लगभग 12,00 यात्री आवाजाही करते है तथा 40 से अधिक ट्रेनों का ठहराव एवं आगमन-प्रस्थान इस स्टेशन से होता है। इस स्टेशन को भविष्य में 25,000 यात्रियों की दैनिक आवाजाही के अनुरूप तैयार किया जा रहा है। आर्थिक और सामरिक महत्वः यह स्टेशन मालगाड़ियों और डबल स्टैक कंटेनर ट्रेनों के आवागमन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जिसका पुनर्विकास स्थानीय समुदाय को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।

सुरक्षित एवं आधुनिक यात्रा अनुभवः इस पुनर्विकास के पूर्ण होने के बाद भीलड़ी स्टेशन यात्रियों को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक अनुभव प्रदान करेगा, जो पश्चिम रेलवे की आधुनिकीकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भारत और कनाडाः कूटनीतिक तनाव से रणनीतिक पुनर्संतुलन की ओर

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की **जीएनएस)।** प्रस्तावित भारत यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत–कनाडा द्विपक्षीय संबंध एक निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं। लगभग दो वर्षों तक चले कूटनीतिक तनाव के बाद, नई दिल्ली और ओटावा दोनों ही अब संबंधों को स्थिर करने और राजनीतिक विश्वास की आंशिक बहाली की दिशा में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं।

भारत और कनाडा के संबंध ऐतिहासिक रूप से कॉमनवेल्थ विरासत, विस्तारित व्यापारिक संपर्कों और कनाडा में बसे सशक्त भारतीय प्रवासी समुदाय पर आधारित रहे हैं। लगभग 18 लाख भारतीय मूल के नागरिक दोनों समाजों के बीच एक स्थायी सेतु का कार्य करते हैं।

फिर भी, हाल के वर्षों की घटनाओं ने इस मजबूत दिखने वाली संरचना के भीतर छिपी कमजोरियों को उजागर किया है।

कूटनीतिक तनाव का चरण

पहला स्पष्ट राजनीतिक विचलन 2020–21 के दौरान भारत में हुए किसान आंदोलनों के समय सामने आया, जब तत्कालीन कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सार्वजनिक रूप से इन आंदोलनों पर चिंता व्यक्त की। भारत सरकार ने इन टिप्पणियों को अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में देखा, जिससे द्विपक्षीय संवाद में असहजता उत्पन्न हुई।

इसके बाद 2022–23 के दौरान तनाव और गहराया, जब भारत ने कनाडा में भारत-विरोधी गतिविधियों, विशेषकर खालिस्तान समर्थक तत्वों द्वारा भारतीय राजनयिक मिशनों को दी गई धमकियों को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की।

सितंबर 2023 में यह संकट उस समय चरम पर पहुँच गया, जब कनाडाई संसद में यह आरोप लगाया गया कि भारत सरकार से जुड़े तत्व एक कनाडाई नागरिक, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल थे। भारत ने इन आरोपों को निराधार और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए सख्ती से खारिज किया।

इस घटनाक्रम का प्रभाव गहरा रहा। दोनों देशों ने अपने राजनयिक कर्मियों की संख्या घटाई और कुछ समय तक उच्चायुक्त स्तर पर प्रतिनिधित्व भी रिक्त रहा। यह प्रकरण केवल एक कूटनीति मतभेद नहीं था, बल्कि आपसी विश्वास में आई गंभीर दरार को दर्शाता था। जब संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे घरेलू राजनीति से टकराते हैं, तो कूटनीतिक संवाद का दायरा स्वतः संकुचित हो जाता है।

रणनीतिक पुनर्संतुलन की दिशा में

कनाडा की घरेलू राजनीति में आए बदलावों के बाद प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अपेक्षाकृत अधिक व्यावहारिक विदेश नीति संकेत दिए। कनाडा की जी7 अध्यक्षता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करना संबंधों को स्थिर करने की दिशा में एक प्रारंभिक संकेत के रूप में देखा गया। भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर एवं कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की

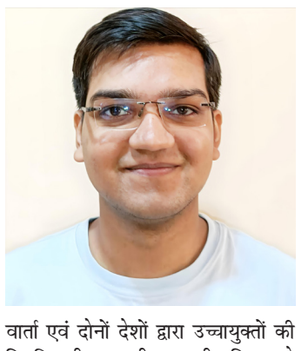

वार्ता एवं दोनों देशों द्वारा उच्चायुक्तों की नियुक्ति भी सामान्यीकरण की प्रक्रिया को दर्शाती है।

हालाँकि, यह पुनर्संतुलन एकतरफा नहीं है। भारत के लिए कनाडा के साथ संवाद उसकी व्यापक विदेश नीति का हिस्सा है, जिसमें सुरक्षा संवेदनशीलताओं और आर्थिक–प्रौद्योगिकीय सहयोग के बीच संतुलन साधना प्रमुख है।

भारत की विदेश नीति आज भी रणनीतिक स्वायत्तता और मुद्दा-आधारित साझेदारियों पर आधारित है, न कि कठोर गुटबद्धताओं पर। इस दृष्टि से भारत–कनाडा संबंधों में यह पुनर्संयोजन भावनात्मक सामंजस्य नहीं, बल्कि व्यावहारिक आवश्यकताओं का परिणाम है।

संबंधों के संरचनात्मक आधार

राजनीतिक उतार-चढ़ाव के बावजूद भारत–कनाडा संबंधों की संरचनात्मक तर्कशीलता बनी हुई है।

* व्यापार और आर्थिक अंतर्संबंध

वर्ष 2024–25 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 9 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया। भारत फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र और इंजीनियर्ड उत्पादों का निर्यात करता है, जबकि कनाडा दालें, उर्वरक और ऊर्जा-संबंधी उपकरण उपलब्ध कराता है। विशेष रूप से कनाडाई दालों का भारत की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है।

* शिक्षा और प्रवासी आयाम

कनाडा भारतीय छात्रों के लिए एक प्रमुख गंतव्य बना हुआ है। 2025 तक लगभग 96,000 भारतीय छात्र वहाँ अध्ययनरत थे। यह शैक्षिक आवागमन न केवल सामाजिक संपर्क बढ़ाता है, बल्कि आर्थिक और ज्ञान-आधारित संबंधों को भी सुदृढ़ करता है।

* महत्वपूर्ण खनिज और ऊर्जा

ऊर्जा सुरक्षा और तकनीकी प्रतिस्पर्धा के वर्तमान दौर में कनाडा के पास उपलब्ध लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, पोटाश और दुर्लभ मृदा तत्व भारत के लिए रणनीतिक महत्व रखते हैं।

विद्युत गतिशीलता, नवीकरणीय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर निर्माण और उन्नत उद्योगों में भारत की आकांक्षाओं के लिए विविध और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाएँ अब केवल आर्थिक नहीं, बल्कि रणनीतिक आवश्यकता बन चुकी हैं।

*वृहत्तर भू-राजनीतिक संदर्भ

संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापारिक और राजनीतिक तनावों के चलते कनाडा ने अपने आर्थिक साझेदारों में विविधता लाने की आवश्यकता को महसूस किया है। दावोस में विश्व आर्थिक मंच के दौरान प्रधानमंत्री कार्नी ने एकतरफा शुल्क व्यवस्थाओं और आपूर्ति श्रृंखला अस्थिरता पर चिंता व्यक्त की।

कार्नी की हालिया चीन यात्रा ने भी कनाडा–अमेरिका संबंधों में निहित तनावों को और स्पष्ट किया, जिससे ओटावा के लिए रणनीतिक संतुलन की आवश्यकता और प्रबल हुई।

इसी व्यापक संदर्भ में भारत–कनाडा संवाद को देखा जाना चाहिए। भारत की बढ़ती आर्थिक क्षमता और वैश्विक मंचों पर उसकी भूमिका ने द्विपक्षीय समीकरण को नया स्वरूप दिया है। आज यह संवाद भारत की सुदृढ़ वैश्विक स्थिति को प्रतिबिंबित करता है, न कि किसी प्रकार की कूटनीतिक अनिवार्यता को।

* एक बहुध्रुवीय अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में प्रभावशाली मध्य शक्तियों के रूप में भारत और कनाडा के हित निम्न क्षेत्रों में अभिसरितः

इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता

क्लीन एनर्जी , हाइड्रोजन और परमाणु सहयोग

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एवं डिजिटल गवर्नेंस

विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान में साझेदारियां

स्थिर सप्लाई चैन

* रणनीतिक परिपक्वता के माध्यम से स्थिरता

फरवरी 2026 में दोनों देशों द्वारा सुरक्षा और कानून-प्रवर्तन संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति पर सहमति इस बात का संकेत है कि संबंधों को संस्थागत आधार पर पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की मुंबई और नई दिल्ली यात्रा टकराव से सावधान पुनर्संतुलन की ओर बढ़ते कदम का प्रतीक है। किंतु दीर्घकालिक सामान्यीकरण तभी संभव होगा जब सुरक्षा चिंताओं का समाधान करते हुए आर्थिक और तकनीकी सहयोग को राजनीतिक अस्थिरताओं से संरक्षित किया जा सके।

यह सहभागिता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस कूटनीतिक दृष्टि को भी प्रतिबिंबित करती है, जो व्यवहारिक सहभागिता (pragmatic engagement) पर आधारित है तथा भारत के सामरिक हितों के अनुरूप साझेदारियों के पुनर्निर्माण पर केंद्रित है।

विखंडित वैश्विक व्यवस्था में भारत और कनाडा आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण, आर्थिक रिज़िलीअन्स और नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में साझा हित रखते हैं। इन संरचनात्मक समानताओं को स्थायी राजनीतिक विश्वास में परिवर्तित करना ही दोनों देशों के संबंधों की भावी दिशा तय करेगा।

लग्जमबर्ग ग्रैंड डची के वित्त मंत्री श्री गिलिस रोथ तथा प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल से शिष्टाचार भेंट की

- मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रूडेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले गुजरात को ग्रीन एनर्जी, ग्रीन फाइनेंसिंग, ग्रीन ग्रोथ में अग्रसरता के लिए लग्जमबर्ग की विशेषज्ञता के लाभ के लिए परामर्श किया
- लॉन्ग टर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आपसी सहयोग को लेकर आयोजित बैठक में चर्चा की गई
- गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल फाइनेंसिंग सेक्टर में निवेश के लिए लग्जमबर्ग की उत्सुकता

जीएनएस)। गांधीनगर : लग्जमबर्ग ग्रैंड डची के वित्त मंत्री श्री गिलिस रोथ तथा प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को गांधीनगर में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल से शिष्टाचार भेंट की। लग्जमबर्ग की 115 बैंकों के साथ एसेट मैनेजमेंट में 8 ट्रिलियन यूरो का निवेश और लगभग 80 देशों में इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में उपस्थिति है। इस संदर्भ में उन्होंने भारत-गुजरात के साथ वित्तीय संबंध विस्तृत करने की उत्सुकता दर्शाई।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस बैठक में हुई चर्चा के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात प्रूडेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला राज्य है। इतना ही नहीं; गुजरात ग्रीन एनर्जी, ग्रीन फाइनेंसिंग तथा ग्रीन ग्रोथ में लीड लेने के लिए सज्ज है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने इस आशय पर विचार-विमर्श किया कि लग्जमबर्ग की ग्रीन बॉण्ड तथा ग्रीन फाइनेंसिंग क्षेत्र की विशेषज्ञता का लाभ गुजरात को मिले। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा रिन्यूएबल-ग्रीन एनर्जी तथा मिशन लाइफ से पर्यावरणानुकूल जीवन शैली के साथ दिए गए ग्रीन ग्रोथ के विचार को म्युनिसिपल ग्रीन बॉण्ड्स तथा लॉन्ग टर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट से साकार किया जा सके; इसके लिए भी मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से आपसी सहयोग की संभावनाएँ तलाशने का अनुरोध किया।

लग्जमबर्ग ग्रैंड डची के वित्त मंत्री श्री गिलिस रोथ ने कहा कि गिफ्ट सिटी में आईएफएससीए तथा लग्जमबर्ग के सीएसएसएफ के बीच हुए एमओयू से भारत एवं लग्जमबर्ग का वित्तीय सहयोग अधिक मजबूत हुआ है और गुजरात की ग्लोबल फाइनेंशियल कनेक्टिविटी में भी वृद्धि हुई है। श्री गिलिस रोथ ने गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल फाइनेंसिंग सेक्टर में अधिक निवेशों के लिए लग्जमबर्ग की उत्सुकता दर्शाई। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने लग्जमबर्ग के प्रतिनिधिमंडल को आगामी जनवरी-2027 में आयोजित होने वाली वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट तथा अप्रैल-2026 व जून-2026 में आयोजित होने वाली दक्षिण एवं मध्य गुजरात की वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का आमंत्रण भी दिया।

श्री गिलिस रोथ ने मुख्यमंत्री तथा गुजरात सरकार के प्रतिनिधिमंडल को लग्जमबर्ग ग्रैंड डची की यात्रा पर आने का भावपूर्ण आमंत्रण दिया।

इस शिष्टाचार बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार, उद्योग आयुक्त श्री पी. स्वरूप तथा मुख्यमंत्री के अपर प्रधान सचिव डॉ. विक्रांत पांडे भी सहभागी हुए।

बजट अपडेट : महिला एवं बाल कल्याण विभाग

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सुपोषित भारत' विजन को वेग देने के लिए महिला एवं बाल कल्याण क्षेत्र में 7,690 करोड़ रुपए का प्रावधान

जीएनएस)। गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सुपोषित भारत' विजन को और वेग देने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल कल्याण क्षेत्र में 7,690 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देने के लिए महिला एवं बाल कल्याण मंत्री डॉ. मनीषाबेन वकील की अध्यक्षता में गांधीनगर में गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन आयोजित हुआ।

आँगनबाड़ी क्षेत्र में ढाँचागत सुधार के लिए राज्य में 2,000 नए आँगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए 360 करोड़ रुपए का प्रावधान।

आँगनबाड़ी केन्द्र 'चाइल्ड फ्रेंड्ली' कॉन्सेप्ट पर बनेंगे; जिनमें मॉड्यूलर फर्नीचर, आरओ मशीन, एलईडी टीवी स्क्रीन तथा रेन वॉटर हार्वेस्टिंग जैसी आधुनिक सुविधाएँ।

आदिजाति क्षेत्रों के 53 घटकों में दूध संजीवनी योजना का विस्तार किया जाएगा। दूध में फैट का प्रमाण 1.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत तथा 4.5 प्रतिशत (पायलट प्रोजेक्ट के रूप में नर्मदा, दाहोद व डांग में) करने के लिए 38.64 करोड़ रुपए का प्रावधान।

कम वजन वाले बच्चों के सुधार के लिए हेल्थ चेकअप तथा होम विजिट के पोषण संगम कार्यक्रमों के लिए 16 करोड़ रुपए।

आँगनबाड़ियों तथा पोषण स्तर की सघन मॉनिटरिंग करने के लिए पोषण प्रगति तथा निरीक्षण केन्द्र बनाए जाएंगे।

आँगनबाड़ी के बच्चों की उपस्थिति एवं मॉनिटरिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम हेतु एआई बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम विकसित किया गया है।

राशन की चोरी रोकने तथा डिजिटल ट्रैकिंग संभव बनाने के लिए पूरक पोषण योजना-टीएचआर की पैकेजिंग पर क्यूआर कोड लगाया जाएगा।

किशोरियों में नेतृत्व के गुण विकसित करने तथा पंचायतीराज एवं बाल अधिकारों के प्रति जागृति लाने के उद्देश्य से बालिका पंचायत योजना अंतर्गत 1.03 करोड़ रुपए का आवंटन।

तहसील, जिला एवं राज्य स्तर पर श्रेष्ठ कार्य करने वाली बालिका पंचायतों को सम्मानित किया जाएगा।

इस संवाददाता सम्मेलन में महिला एवं बाल कल्याण विभाग के सचिव श्री राकेश शंकर सहित विभाग के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना

'आत्मा गांव की, सुविधा शहर की' आधुनिक तथा आदर्श गांवों की दिशा में पहल

जीएनएस)। गांधीनगर : पीने के पानी, कूड़ा प्रबंधन तथा गंदे पानी के उपचार जैसी आधारभूत सुविधाओं का विकास। मुख्य तथा आंतरिक मार्गों के निर्माण द्वारा सशक्त परिवहन व्यवस्था। ई-लाइब्रेरी, खेल के मैदान तथा तालाब के आसपास वॉक-वे जैसी आधुनिक सुविधाओं का समावेश। स्ट्रीट लाइट तथा सार्वजनिक शौचालय जैसी नागरिक सुविधाओं से गांवों को सुसज्जित बनाने का उद्देश्य। चयनित गांवों में आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं का संतृप्ति स्तर सुनिश्चित करने का लक्ष्य। वर्ष 2026–27 के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान ग्रामीण क्षेत्रों को आधुनिक और सुविधासंपन्न बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम

पश्चिम रेलवे – रतलाम मंडल

ई-टेंडरिंग नोटिस

संख्या- W/623/5/1/NIT दिनांक: 23.02.2026

मण्डल रेल प्रबंधक/मण्डल कार्यालय (कार्यलेखा शाखा) पश्चिम रेलवे रतलाम भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्य के लिये "खुली निविदा" ई-निविदा के माध्यम से वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर आमंत्रित करते है। विवरण इस प्रकार है-

क्र. सं.	ई-टेंडरिंग संख्या और कार्य का नाम	अनुमानित लागत रू	बयाना राशि रू	कार्य समापन अवधि
1	**RTM-2025-26-193**	**2,20,78,626.24**	**2,60,400/-**	12 माह
	Ratlam- Providing 10 units type II quarters in lieu of abandoned non standard quarters T-6 (A-J), Composite (Civil +Electrical) **Similar type of work: Construction of any Building work.**			
2	**RTM-2025-26-198**	**4,50,54,870.73**	**3,75,300/-**	09 माह
	Ujjain -Naikhedi - Providing Boundary Wall to prevent encroachment and tress passing in connection with Simhastha 2028 (Total 4.24 KM) **Similar type of work: Any Civil Engineering Work.**			

अनुमानित मात्रा: As per tender schedule. वेबसाईट पर अपलोड करने की तिथि: 23.02.2026. निविदा खुलने की तिथि: 20.03.2026. विस्तृत निविदा सूचना, अहाता शर्तें एवं अन्य शर्तें वेबसाइट www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है। AK/5/1/479

हमें लाईक करें: facebook.com/WesternRly • हमें फॉलो करें: X.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे – रतलाम मंडल

ई-टेण्डरिंग नोटिस

संख्या- W/623/5/1/NIT दिनांक: 24.02.2026

मण्डल रेल प्रबंधक/मण्डल कार्यालय (कार्यलेखा शाखा) पश्चिम रेलवे रतलाम भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्य के लिये "खुली निविदा" ई-निविदा के माध्यम से वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर आमंत्रित करते है। विवरण इस प्रकार है-

क्र. सं.	ई-टेंडरिंग संख्या और कार्य का नाम	अनुमानित लागत रू	बयाना राशि रू	कार्य समापन अवधि
1	**RTM-2025-26-147**	**20,43,92,501.36**	**11,72,000/-**	18 माह
	1. Pawasa: Provision of new "B" class station between UJN and PLW in connection with Simhastha 2028 including electrical works. **2.** Vikram Nagar - Extension of machine Siding and dead ends of Line Number 1 to stable full length trains in connection of Simhastha 2028. **3.** Sehore-Direct Entry and Exit facility at Sehore Goods shed Line including electrical works. **4.** Vikramnagar - CTR (P) of Line no. 5 (0.9 Tkm). **Similar type of work: As per Special Technical Criteria enclosed in Tender Schedule.**			

वेबसाईट पर अपलोड करने की तिथि: 24.02.2026. निविदा खुलने की तिथि: 18.03.2026. विस्तृत निविदा सूचना, अहाता शर्तें एवं अन्य शर्तें वेबसाइट www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र का मुल्य Nil है। AK/5/1/483

हमें लाईक करें: facebook.com/WesternRly • हमें फॉलो करें: X.com/WesternRly

बजट अपडेट – ऊर्जा विभाग

गुजरात वायर फ्री सिटी मिशन अंतर्गत महानगर पालिका तथा नगर पालिका क्षेत्रों में ओवरहेड विद्युत नेटवर्क को भूमिगत केबल नेटवर्क में रूपांतरित करने के लिए 500 करोड़ रुपए का नया प्रावधान

जीएनएस)। गांधीनगर : राज्य के विकास एवं नागरिकों की बढ़ती विद्युत मांग को ध्यान में रखते हुए निर्बाध्य, सुरक्षित तथा उच्च गुणवत्तायुक्त विद्युत आपूर्ति बनाए रखना अत्यंत आवश्यक हो गया है।

इस पहल से राज्य के नागरिकों तथा अस्पतालों, स्वास्थ्य केन्द्रों, जलापूर्ति, बस अड्डों, पुलिस थानों आदि जैसी आवश्यक सेवाओं को विक्षेप रहित तथा विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति निर्बाध्य रूप से मिलेगी।

इस पहल से पावर विक्षेपों में कमी आएगी, शहरी घने क्षेत्रों में अधिक सुरक्षित एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी इस मिशन से खुले वायरों से होने वाली दुर्घटनाओं के निवारण में भी काफी मदद मिलेगी। यह पहल गुजरात को अधिक सुव्यवस्थित तथा स्मार्ट शहरी राज्य के रूप में आगे बढ़ाएगी।

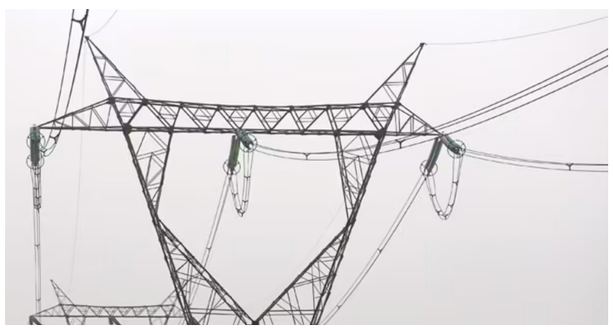

राज्य को कॉमनवेल्थ तथा ओलंपिक रेडी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसके अंतर्गत चरणबद्ध ढंग से सभी महानगर पालिका तथा नगर पालिका क्षेत्रों को वायर फ्री सिटी में रूपांतरित किया जाएगा।

राज्य के यात्राधाम क्षेत्रों को ग्रीन तथा विद्युत सुरक्षित जोन में विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान

जीएनएस)। गांधीनगर : यात्राधामों में निरंतर तथा गुणवत्तायुक्त विद्युत आपूर्ति बनी रहे, विद्युत सुरक्षा का स्तर बढ़े और स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहन मिले; इस उद्देश्य से विद्युत वितरण ढाँचे का आधुनिकीकरण किया जाएगा। रूफटॉप सोलर सिस्टम का प्रचार तथा कार्बन उत्सर्जन में कमी

पर्यटन तथा मंदिर के कामकाज और त्योहारों के दौरान विश्वसनीय एवं निरंतर विद्युत आपूर्ति बनी रहेगी।

अंडरग्राउंड नेटवर्क, व्यवस्थित वितरण प्रणाली और आधुनिक सुविधाओं के जरिये यात्राधामों के सौंदर्य में वृद्धि

सरकारी भवनों तथा लोकल ऑथोरिटी के भवनों पर अधिकतम् 50 किलोवाट क्षमता तक के रूफटॉप सोलर सिस्टम इन्स्टॉलेशन के लिए राज्य की सोलर सब्सिडी सहायता

यह योजना विद्युत वितरण नवीनीकरण के जरिये नेटवर्क को अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय तथा आधुनिक बनाने के लिए है, जिसमें केबलिंग, ट्रांसफॉर्मर अपग्रेड तथा मेंटनेंस पर विशेष ध्यान दिया गया है।

प्रारंभिक चरण में द्वारका, सोमनाथ, अंबाजी तथा पालीताणा यात्राधामों के क्षेत्रों को प्राथमिकता देकर ग्रीन एवं विद्युत सुरक्षित जोन में विकसित करने की योजना प्रस्तुत की गई है।

यात्रियों की विद्युत सुरक्षा तथा यात्राधामों को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य होगा।

पश्चिम रेलवे – रतलाम मंडल

ई- निविदा सूचना

वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर, कर्षण वितरण, रतलाम मंडल, पश्चिम रेलवे भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु IREPS पोर्टल के माध्यम से खुली निविदाएं आमंत्रित करते हैं: **निविदा संख्या: EL/TRD/58/2x25/EPC-PSI/01, दिनांक: 24.02.2026. कार्य का नाम:** Design, Supply, Erection, Testing and Commissioning of 132/55KV Scott Connected Traction Substation and Switching Posts for 2x25KV feeding system between Godhra-Ratlam section of Ratlam Division of Western Railway. **अनुमानित लागत:** रु. 146,06,00,000/-. **बयाना राशि:** रु. 74,53,000/-. **समापन अवधि:** 24 Months. **निविदा दस्तावेज़ की राशि:** Nil. **ऑनलाइन बिडिंग बंद होने की दिनांक एवं समय:** 12.03.2026 upto 15:00 hrs की जगह 25.03.2026 upto 15:00 hrs. **तकनीकी बोलियां खोलने की की दिनांक एवं समय:** 24.03.2026 upto 15:30 hrs की जगह 06.04.2026 upto 15:30 hrs. **ऑफर की वैधता:** 180 days from the date of opening. **वेबसाइट: www.ireps.gov.in नोटिस बोर्ड:** वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर, कर्षण वितरण, रतलाम मंडल, पश्चिम रेलवे के कार्यालय के प्रवेश द्वार के सामने। AK/13/1/482

हमें लाईक करें: facebook.com/WesternRly

साणंद में माइक्रोन का मेगा सेमीकंडक्टर प्लांट एआई टेक्नोलॉजी के भविष्य को सशक्त बनाएगा

▸▸ साणंद के प्लांट में बनेंगे एसएसडी तथा रैम प्रकार के स्टोरेज एवं मेमोरी उपकरण

▸▸ 2000 लोगों की टीम कार्यरत, आगामी समय में 5 हजार लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा, दिव्यांग नागरिकों के लिए भी नौकरी के अवसर उपलब्ध

▸▸ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में शुरू हुई क्रांति में गुजरात नेतृत्व की भूमिका में

जीएनएस)। गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के भगीरथ प्रयासों से भारत अब नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन अंतर्गत सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन क्षेत्र में भी डंका बजाने को तैयार है। आगामी 28 फरवरी, 2026 को गुजरात के साणंद में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी माइक्रोन टेक्नोलॉजी के अत्याधुनिक एटीएमपी (असेम्बली, टेस्टिंग, मार्किंग एवं पैकेजिंग) प्लांट का उद्घाटन करेंगे। साणंद में माइक्रोन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया प्रा. लि. द्वारा 22,516 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और गुजरात में माइक्रोन की एटीएमपी सुविधा के शुरू होने से भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में नई क्रांति का शुभारंभ होगा।

माइक्रोन के साणंद प्लांट में 2000 लोगों की टीम कार्यरत, दिव्यांग नागरिकों के लिए भी अवसर

सेमीकंडक्टर क्षेत्र में गुजरात समग्र देश में नेतृत्व की भूमिका में है और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के सघन प्रयासों से साणंद में माइक्रोन का प्लांट निर्धारित समयसीमा में कार्यरत होने जा रहा है। यह प्लांट एक एटीएमपी सुविधा है; जिसमें एसएसडी (सॉलिड स्टेट ड्राइव-हार्ड डिस्क प्रकार के स्टोरेज के लिए आधुनिक उपकरण) तथा रैम प्रकार के डीआरएएम एवं एनएएनडी उत्पाद तैयार किए जाएंगे। साणंद प्लांट में हाल में 2000 लोगों की टीम कार्यरत है, जिसमें आगामी समय में 5 हजार लोगों को सीधे रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। माइक्रोन टीम के कथनानुसार यहाँ दिव्यांग नागरिक भी ऑपरेटर तथा टेक्निशियन के रूप में कार्य करते हैं और कौशल से सज्ज सभी तरह के नागरिकों के लिए नौकरी के अवसर उपलब्ध हैं।

साणंद प्लांट में तैयार होने वाले उत्पाद एआई टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी

एटीएमपी प्लांट में किस प्रकार कार्य होता है ?

एटीएमपी प्लांट का कार्य वेफर चिप्स से शुरू होता है। सबसे पहले हम ये समझें कि एटीएमपी सविधा तक पहुँचने से पहले ये चिप्स किस तरह बनती हैं। सेमीकंडक्टर चिप बनाने की प्रक्रिया रेत (सैंड) से शुरू होती है। सबसे पहले रेत से प्योर सिलिकॉन को अलग किया जाता है। इस सिलिकॉन को पिघलाकर उसका सिलेंडर बनाया जाता है, जिसे इनगोट कहा जाता है। इस सिलेंडर को काटकर उसमें से सूक्ष्म प्लेट्स बनाई जाती हैं, जिसे वेफर्स कहा जाता है। इसके बाद फैब्रिकेशन प्लांट में इन वेफर्स पर इलेक्ट्रिक पैटर्न प्रिंट किया जाता है और कई आवरण (लेयर्स) उस पर चढ़ाए जाते हैं। इन आवरणों को फोटोलिथोग्राफी द्वारा उचित ढंग से नियोजित करने से वेफर्स पर ट्रांजिस्टर्स बनते हैं। इसके द्वारा वेफर्स पर मेमोरी बनती है और इन वेफर्स में मेमोरी चिप लगाई जाती है। इसके बाद वेफर्स के छोटे चौकोर टुकड़े किए जाते हैं, जिसे चिप कहा जाता है।

यह चिप इसके बाद एटीएमपी प्लांट में पहुँचती है। यहाँ पहले उसे असेम्बल किया जाता है। इसके बाद टेस्टिंग के चरण में उसकी स्पीड, मेमोरी तथा कार्य की संपूर्ण टेस्टिंग की जाती है। इसके बाद उसकी विवरणबद्ध मार्किंग कर अंत में उसकी पैकेजिंग की जाती है, जिससे वह मार्केट में पहुँच सके। साणंद प्लांट में विश्वभर के मार्केट के अनुरूप इंटीग्रेटेड सर्किट पैकेज, मॉड्यूल तथा सॉलिड स्टेट ड्राइव्स का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए माइक्रोन की वैश्विक फैक्ट्रियों में निर्मित अत्याधुनिक डीआरएएम तथा एनएनडी वेफर्स मिलाकर उन्हें फाइनल मेमोरी उत्पादों में परिवर्तित किया जाएगा। ये उत्पाद एआई क्षेत्र में मेमोरी तथा स्टोरेज की बढ़ रही मांग को पूर्ण करने में सहायक होंगे।

माइक्रोन टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष तथा सीईओ श्री संजय मेहरोत्रा ने कहा कि वर्तमान टेक्नोलॉजी में; विशेषकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में मेमोरी एवं स्टोरेज बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि मजबूत मेमोरी तथा स्टोरेज सपोर्ट के बिना एआई प्रणालियाँ उचित ढंग से कार्य नहीं कर पाती हैं। जैसे-जैसे एआई अधिक तेज एवं रियल-टाइम रिस्पॉन्स देना शुरू करता है, वैसे-वैसे उसे अधिक तथा और अत्याधुनिक मेमोरी की जरूरत पड़ती है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के प्राकृतिक खेती से नए जुड़े किसानों को प्रोत्साहन के रूप में 6.97 करोड़ रुपए की सहायता डीबीटी के माध्यम से बैंक खातों में जमा कराई

▸▸ कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी तथा कृषि राज्य मंत्री श्री रमेशभाई कटारा की उपस्थिति

▸▸ नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग द्वारा खरीफ एवं रबी मौसम के लिए प्रति एकड़ दो हजार रुपए की सहायता दी जाती है

▸▸ तीन ग्राम पंचायतों पर एक क्लस्टर अंतर्गत समग्र राज्य में 1015 क्लस्टर में प्राकृतिक खेती करने के इच्छुक किसानों को प्रशिक्षण-मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है

▸▸ प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों ने भावी पीढ़ी को सुरक्षित करने का आत्मसंतोष प्राप्त हो; ऐसा कार्य किया है

▸▸ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वस्थ जीवन के लिए बैक टू बेसिक मंत्र अपनाकर प्राकृतिक खेती को मिशन मोड में अपनाने का आह्वान किया है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

जीएनएस)। गांधीनगर : राज्य में प्राकृतिक खेती का दायरा बढ़े तथा अधिकाधिक किसान यह खेती अपनाएँ; इसके लिए नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग द्वारा किसानों को प्रोत्साहक सहायता दी जाती है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस संदर्भ में राज्य में प्राकृतिक खेती से नए जुड़े 33 जिलों के 35,829 किसानों को गुरुवार को नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग अंतर्गत खरीफ मौसम हेतु एक एकड़ के लिए 2000 रुपए की सहायता का प्रत्यक्ष लाभांतरण (डीबीटी) से वितरण किया। कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी तथा कृषि राज्य मंत्री श्री रमेशभाई कटारा की उपस्थिति में गांधीनगर में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने कुल 6.97 करोड़ रुपए की प्रोत्साहक सहायता सिंगल क्लिक से किसानों के बैंक खातों में जमा कराई।

राज्य में प्राकृतिक खेती का दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से तीन ग्राम पंचायतों पर एक क्लस्टर; इस प्रकार बने कुल 1015 क्लस्टर में प्राकृतिक खेती करने के इच्छुक किसानों को प्रशिक्षण, मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहक सहायता प्रदान किए जाते हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों को स्वास्थ्यप्रद जीवन के लिए बैक टू बेसिक का मंत्र अपनाकर प्राकृतिक खेती को मिशन मोड पर अपनाने और ऐसी खेती से उत्पादित उत्पादों के व्यापक उपयोग का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने किसानों को प्रेरणा देते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती अपनाकर भावी पीढ़ी को सुरक्षित करने का आत्मसंतोष प्राप्त हो; ऐसा कार्य इन धरतीपुत्रों ने किया है।

श्री पटेल ने यह भी कहा कि राज्यपाल आचार्य देवव्रतजी ने राज्य के किसानों को गाय आधारित प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करने का जन आंदोलन चलाया है। वे गाँव-गाँव जाकर इसके लिए मार्गदर्शन भी दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती अब जब समय की मांग और हमारे स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य बन गई है, तब हम जितना जल्दी इस खेती की ओर मुड़ेंगे, उतना जल्दी फायदा मिलेगा।

कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने कहा कि किसान देसी गाय आधारित तथा सरलता से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर रसायनमुक्त खेती करने लगें; इसके लिए भारत सरकार ने समग्र देश में नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग शुरू कराया है।

श्री वाघाणी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में हमने राज्य में इस मिशन के तहत तीन ग्राम पंचायतों पर एक के हिसाब से कुल 1015 क्लस्टर कार्यरत किए हैं और शेष ग्राम पंचायतों में भी नॉन-मिशन अंतर्गत हर तीन ग्राम पंचायत पर एक के हिसाब से कुल 3875 क्लस्टर का गठन किया जाएगा। इस प्रकार; कुल लगभग 4890 क्लस्टर के गठन से प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहन देने की योजना है।

उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं; किसानों को प्राकृतिक खेती की प्रत्यक्ष जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 7100 मॉडल फार्म का निर्माण हुआ है। इस वर्ष के बजट में भी प्राकृतिक खेती की विभिन्न गतिविधियों के लिए राज्य सरकार ने 392 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

समारोह में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव श्री आर. सी. मीणा, गुजरात एग्रो के प्रबंध निदेशक श्री विजय खराडी, कृषि निदेशक श्री राजेन्द्रसिंह राजपूत, गुजरात प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड के श्री पटेल, अधिकारी तथा लाभार्थी ग्रामीण किसान उपस्थित रहे।

पश्चिम रेलवे द्वारा वड़ोदरा मंडल पर "संवाद" का सफल आयोजन

जीएनएस)। दिनांक 26.02.2026 को पश्चिम रेलवे के वाणिज्य विभाग द्वारा वडोदरा मंडल पर एक "संवाद" कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री तरुण जैन, प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, पश्चिम रेलवे ने की एवं इस अवसर पर मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (मालभाड़ा) श्री जेरिन जी. आनंद तथा वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, वडोदरा श्री नरेंद्र कुमार भी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में मुंबई, वडोदरा, रतलाम, अहमदाबाद, राजकोट एवं भावनगर मंडलों से लगभग 50 से अधिक फील्ड कर्मचारियों ने भाग लिया। संवाद के दौरान वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों ने अपने दैनिक कार्य में आने वाली समस्याओं को प्रमुखता से पटल पर रखा तथा उनके व्यावहारिक समाधान भी सुझाए। इस संवाद में भविष्य में पार्सल और माल राजस्व में वृद्धि हेतु नए सुझावों पर भी गहन चर्चा की गई। यह पहल फील्ड कर्मचारी एवं उच्च प्रबंधन के मध्य एक समन्वय स्थापित करने में एक कड़ी का कार्य करेगी एवं रेल राजस्व की वृद्धि करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए वातानुकूलित लोकल सेवाओं में वृद्धि

जीएनएस)। पिछले कुछ वर्षों में पश्चिम रेलवे पर वातानुकूलित (एसी) लोकल ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यात्रियों की बढ़ती लोकप्रियता और मांग को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे मुंबई उपनगरीय खंड में वातानुकूलित लोकल सेवाओं की संख्या निरंतर बढ़ा रही है। वर्तमान में पश्चिम रेलवे द्वारा अपने उपनगरीय नेटवर्क पर सोमवार से शुक्रवार 133 एसी लोकल सेवाएं संचालित की जा रही है। वहीं शनिवार और रविवार को 106 एसी लोकल सेवाएं चलाई जा रही हैं, जिससे सप्ताहांत में यात्रा करने वाले यात्रियों को अधिक सुविधा और आराम मिल रहा है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, इस वर्ष कई नई लोकल सेवाएं शुरू की गई हैं, जिनमें एसी सेवाएं भी शामिल हैं। जनवरी माह में 12 एसी लोकल सेवाएं शुरू की गईं तथा फरवरी में 12 और सेवाएं जोड़ी गईं। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे पर एसी सेवाओं की कुल संख्या बढ़कर 133 हो गई है। एसी सेवाओं की बढ़ी हुई संख्या से यात्रियों को सप्ताहांत में भी सुविधाजनक, आरामदायक और वातानुकूलित यात्रा का अनुभव मिल रहा है। श्री विनीत ने आगे बताया कि एसी लोकल ट्रेनें बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करती हैं और उपनगरीय नेटवर्क के विभिन्न वर्गों के यात्रियों से इन्हें लगातार सकारात्मक प्रतिसाद मिल रहा है। सप्ताहांत पर अतिरिक्त एसी सेवाओं की उपलब्धता से विशेष रूप से उन यात्रियों को लाभ हुआ है जो कार्यालय, अवकाश या अन्य व्यक्तिगत कार्यों के लिए यात्रा करते हैं। साथ ही, इससे आगामी ग्रीष्म ऋतु में भी यह यात्रियों के लिए बड़ी राहत मिलेगी। पश्चिम रेलवे सुरक्षित, कुशल और यात्री-अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। एसी लोकल सेवाओं की बढ़ी हुई उपलब्धता दैनिक यात्रा की गुणवत्ता में सुधार करने और मुंबई की जीवनरेखा को और सुदृढ़ बनाने के इसके निरंतर प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

साणंद जीआईडीसी में प्रीमियम होटल बनाने के लिए प्लॉट की नीलामी पूर्ण, लगभग 5 एकड़ भूमि डेवलपर को आवंटित

▸▸ चार वर्ष में निर्माण कार्य का प्रावधान, साणंद औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों को मिलने वाली सुविधाओं में वृद्धि

▸▸ गुजरात में सेमीकंडक्टर क्षेत्र तथा औद्योगिक इकोसिस्टम के विकास के लिए राज्य सरकार सतत प्रयत्नशील

जीएनएस)। गांधीनगर : साणंद औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत नेशनल तथा मल्टीनेशनल कंपनियों की सुविधाओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से होटल निर्माण के लिए प्लॉट की नीलामी पूर्ण की गई है। साणंद-2 औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 20168.54 वर्ग मीटर (अनुमानित 5 एकड़) प्लॉट विशेष रूप से प्रीमियम होटल निर्माण के लिए रिजर्व किया गया था, जिसकी नीलामी गत 22 दिसंबर, 2025 को पूर्ण की गई है।

इस ई-नीलामी में अधिकतम बिड के साथ

डेवलपर को नियमों के अनुसार प्लॉट का आवंटन किया गया है। 3 से 5 स्टार होटल के निर्माण का कार्य शुरू करने के लिए कंपनी को चार वर्ष का मोरेटोरियम पीरियड दिया गया है। इस होटल के अतिरिक्त; साणंद औद्योगिक क्षेत्र के 3 किलोमीटर निकट एक फाइव स्टार होटल के निर्माण का कार्य भी प्रगति पर है। आगामी 28 फरवरी, 2026 को साणंद औद्योगिक क्षेत्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी माइक्रोन टेक्नोलॉजी के अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ कराएंगे। इस प्रकार की विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनियों की उपस्थिति होने के कारण यहाँ की यात्रा पर आने वाले डेलीगेट्स तथा कर्मचारियों के रहने के लिए यह होटल सुविधा महत्वपूर्ण सिद्ध बनेगी। राज्य में उद्योगों की जरूरत के अनुरूप सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए भी मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में सघन प्रयास चल रहे हैं।

साणंद औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों की सुविधा के लिए अत्याधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है। यहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सुव्यवस्थित कनेक्टिविटी होने के कारण उद्योगों का निरंतर विकास हो रहा है। हाल में साणंद औद्योगिक क्षेत्र में 1150 औद्योगिक इकाइयाँ कार्यरत हैं। साणंद में महिलाओं के लिए समर्पित महिला औद्योगिक पार्क बनाया गया है, जिसके द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने उद्योगों के लिए अनुकूल नीतियाँ बनाकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के विजन को चरितार्थ किया है।

क्रूड ऑयल वायदा 119 रुपये फिसला: सोना वायदा में 1983 रुपये और चांदी वायदा में 9449 रुपये की गिरावट

▸▸ कमोडिटी वायदाओं में 24367.08 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 298684.89 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 20046.33 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 39750 पॉइंट के स्तर पर

जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 323052.21 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 24367.08 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 298684.89 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का मार्च वायदा 39750 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 1793.66 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 20046.33 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 160530 रुपये के भाव पर खूलकर, 160858 रुपये के दिन के उच्च और 159106 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 161145 रुपये के पिछले बंद के सामने 1983 रुपये या 1.23 फीसदी लुढ़ककर 159162 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। गोल्ड-गिनी मार्च वायदा 1210 रुपये या 0.93 फीसदी घटकर 129571 रुपये प्रति 8 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-पेटल मार्च वायदा 136 रुपये या 0.83 फीसदी घटकर 16324 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। सोना-मिनी मार्च वायदा 158427 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 158510 रुपये और नीचे में 156870 रुपये पर पहुंचकर, 1949 रुपये या 1.23 फीसदी घटकर 156969 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-टेन मार्च वायदा प्रति 10 ग्राम 160998 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 161309 रुपये और नीचे में 159769 रुपये पर पहुंचकर, 161517 रुपये के पिछले बंद के सामने 1668 रुपये या 1.03 फीसदी घटकर 159849 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 264300 रुपये के भाव पर खूलकर, 266800 रुपये के दिन के उच्च और 255172 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 268316 रुपये के पिछले बंद के सामने 9449 रुपये या 3.52 फीसदी की गिरावट के साथ 258867 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। इनके अलावा चांदी-मिनी अप्रैल वायदा 11655 रुपये या 4.14 फीसदी औंधकर 269750 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि चांदी-माइक्रो अप्रैल वायदा 11509 रुपये या 4.09 फीसदी गिरकर 269899 रुपये प्रति किलो हुआ।

मेटल वर्ग में 2539.92 करोड़ रुपये के

ट्रेड दर्ज हुए। तांबा मार्च वायदा 8.85 रुपये या 0.73 फीसदी घटकर 1202.5 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि जस्ता मार्च वायदा 2.6 रुपये या 0.79 फीसदी की गिरावट के साथ 325.9 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। इसके सामने एल्यूमीनियम मार्च वायदा 1.8 रुपये या 0.57 फीसदी औंधकर 311.35 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा मार्च वायदा 1.05 रुपये या 0.55 फीसदी घटकर 188.9 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 1674.09 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल मार्च वायदा 5978 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 5983 रुपये और नीचे में 5856 रुपये पर पहुंचकर, 119 रुपये या 1.99 फीसदी घटकर 5870 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी मार्च वायदा 116 रुपये या 1.94 फीसदी लुढ़ककर 5871 रुपये प्रति बैरल बोला गया। इनके अलावा नैचुरल गैस मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 261.6 रुपये के भाव पर खूलकर, 262.2 रुपये के दिन के उच्च और 254.5 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 264.5 रुपये के पिछले बंद के सामने 9.5 रुपये या 3.59 फीसदी की गिरावट के साथ 255 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि नैचुरल गैस-मिनी मार्च वायदा 9.6 रुपये या 3.63 फीसदी गिरकर 255.1 रुपये प्रति एमएमबीटीयू हुआ। कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल मार्च वायदा 961.1 रुपये पर खूलकर, 3.7 रुपये या 0.39 फीसदी घटकर 957 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 9823.35 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 10222.98 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 2143.96 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 150.28 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 15.79 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 226.46 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 683.68 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 965.15 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 1.00 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन केंडी के वायदाओं में 0.13 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 9385 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 74691 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 29553 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 366823 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 50917 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 9724 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 17056 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 58900 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 17751 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 30183 लोट के स्तर पर था। इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 39750 पॉइंट पर खूलकर, 39750 के उच्च और 39750 के नीचले स्तर को छूकर, 430 पॉइंट घटकर 39750 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल मार्च 6000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 49.2 रुपये की गिरावट के साथ 271.5 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मार्च 260 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 4.7 रुपये की गिरावट के साथ 14.85 रुपये हुआ।

सोना फरवरी 160000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 1264 रुपये की गिरावट के साथ 680 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मार्च 300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 5438 रुपये की गिरावट के साथ 11856.5 रुपये हुआ। तांबा मार्च 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 5.79 रुपये की गिरावट के साथ 41.01 रुपये हुआ। जस्ता मार्च 340 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 86 पैसे की नरमी के साथ 3.64 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल मार्च 5900 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 64 रुपये की बढ़त के साथ 340.5 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मार्च 260 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 5.5 रुपये की बढ़त के साथ 20.4 रुपये हुआ।

सोना फरवरी 150000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 4 रुपये की गिरावट के साथ 44 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मार्च 260000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 3130.5 रुपये की बढ़त के साथ 19000 रुपये हुआ। तांबा मार्च 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 3.21 रुपये की बढ़त के साथ 37.24 रुपये हुआ। जस्ता मार्च 315 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 39 पैसे के सुधार के साथ 3.49 रुपये हुआ।